सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 273, नई दिल्ली । गुरुवार, 12 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे: सर्दी की चेतावनी

06 सफल लोग अलग तरह से काम करते हैं

08 *वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत: सरकार की नई योजनाएं लागू*

# नितिन गडकरी का एलान- अगले पांच साल में भारत वैश्विक ऑटो उद्योग का करेगा नेतृत्व

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया है कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर नंबर एक स्थान पर पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रेखांकित किया कि दो वर्षों में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को 9 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

**नई दिल्ली।** मंगलवार को अमेजन संभव शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की उल्लेखनीय बढ़ोतरी का जिक्र किया। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके पदभार संभालने के बाद से यह 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

**तीसरे नंबर से पहले पर आना है**

उन्होंने कहा, "पहला स्थान अमेरिका का है - 78 लाख करोड़ रुपये का, दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग चीन में है - 47 लाख करोड़ रुपये का, और अब भारत 22 लाख करोड़ रुपये का है। मुझे विश्वास है कि 5 साल के भीतर हम भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं।"

**भारत में लॉजिस्टिक्स लागत**

मंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिष्ठित वैश्विक ऑटोमोबाइल ब्रांडों की मौजूदगी देश की क्षमता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य 2 वर्षों के भीतर भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को एक अंक तक कम करना है।

उन्होंने कहा, "भारत में लॉजिस्टिक लागत 16 प्रतिशत है और चीन में यह 8 प्रतिशत है, अमेरिका और यूरोपीय देशों में यह 12 प्रतिशत है। सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने का निर्णय लिया है... मेरे मंत्रालय में हमारा लक्ष्य है कि 2 वर्षों के भीतर हम इस लॉजिस्टिक लागत को 9 प्रतिशत तक ले जाएंगे।"

**यात्रा समय होगा कम**

गडकरी ने उन खास परियोजनाओं पर रोशनी डाली, जो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय में भारी कमी लाएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से देहरादून की यात्रा, जो वर्तमान में लगभग नौ घंटे की होती है, जनवरी 2025 तक घटकर मात्र दो घंटे की रह जाएगी। इसी तरह, दिल्ली-मुंबई और चेन्नई-बंगलूरू के बीच यात्रा के समय में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

**ईंधन की लागत कम करना है**

इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। और कहा कि वाहनों में बायो-इथेनॉल का उपयोग करने से ईंधन की लागत में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।

गडकरी ने एडवांस्ड रिसाइकिलिंग टेक्नोलॉजी (उन्नत पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों) के जरिए जैविक कचरे को हाइड्रोजन ईंधन और अन्य मूल्यवान सामग्रियों में बदलने की योजनाओं की रूपरेखा भी पेश की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भारी मात्रा में नगरपालिका अपशिष्ट पैदा होता है। जिसमें से वर्तमान में सिर्फ 80 लाख टन का ही उपयोग किया जा रहा है।

**जैविक कचरे से हाइड्रोजन**

गडकरी ने कहा, "हमारा विचार जैविक कचरे से हाइड्रोजन बनाना है। कचरे को अलग करके हम पेट्रोल, प्लास्टिक, धातु और कांच हासिल कर सकते हैं। इन सभी उपलब्ध सामग्रियों की रिसाइकिलिंग संभव है।

उन्होंने कहा, "और एक और तकनीक है जिसके द्वारा हम इस कचरे का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन हासिल करने के लिए कर सकते हैं।"

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

# हिमाचल प्रदेश सरकार बनाएगी ग्रीन कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देगी बढ़ावा

परिवहन विशेष न्यूज

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पांच चयनित ग्रीन कॉरिडोर (हरित गलियारों) में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दो कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पांच चयनित ग्रीन कॉरिडोर (हरित गलियारों) में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दो कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

जारी बयान में कहा गया कि परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी की ओर से राहुल सोनी और जियो-बीपी की ओर से अविनाश शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

सुक्खू ने कहा कि निविदा समझौते के अनुसार जियो-बीपी मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट और कीरतपुर-मनाली-केलांग कॉरिडोर विकसित करेगी। जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी परवाणू-ऊना-संसारपुर-टैरेस-नूरपुर और परवाणू-शिमला-रिकांगपिओ-लोसर कॉरिडोर का काम एक साल के भीतर पूरा करेगी।

इसके अलावा इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने पर काम करेगी। परियोजना के तहत कंपनियां एक साल के भीतर इन कॉरिडोर के साथ 41 रणनीतिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपरमार्केट स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों, ई-ट्रकों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन 41 स्थानों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा, इन स्थानों पर शौचालय और रेस्तरां जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। और कंपनियां राज्य सरकार को सालाना 75 लाख रुपये लीज मनी के रूप में देंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट (हरित ऊर्जा राज्य) बनाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए सरकार राज्य को ई-वाहनों के लिए मॉडल राज्य के रूप में विकसित कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 350 ई-बसें खरीदने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा संचालित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इन ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना से निजी वाहन मालिकों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

# बेस्ट ने ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य करने का लिया फैसला; निजी ऑपरेटरों के साथ की बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई के कुर्ला में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद जागते हुए बेस्ट ने बैठकों का दौर शुरू किया है। आज निजी ऑपरेटरों के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला ये है कि बेस्ट बसों के ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य होगा।

मुंबई की नागरिक परिवहन संस्था बेस्ट ने कुर्ला सड़क हादसे के मद्देनजर ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को उन निजी ऑपरेटरों से मुलाकात की जो सरकारी एजेंसियों को बसें उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने ड्राइवरों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाने की बात कही।

**बेस्ट ने निजी ऑपरेटरों के साथ की बैठक**

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की इलेक्ट्रिक बस के बेकाबू होकर उपनगरीय कुर्ला (पश्चिम) में पैदल यात्रियों और वाहनों को टक्कर मारने के दो दिन बाद, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए, अधिकारियों ने वेट लीज मॉडल के तहत बसें उपलब्ध कराने वाले निजी ऑपरेटरों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि बैठकों में निजी ऑपरेटरों से ड्राइवरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण, उनकी नियुक्ति के मानदंड, प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और मॉड्यूल का विवरण देने को कहा गया।

**हादसे के बाद जागा बेस्ट, बैठकों का दौर जारी**

बेस्ट और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के शीर्ष अधिकारियों ने इन बैठकों की अध्यक्षता की। वेट लीज मॉडल के तहत, ड्राइवर उपलब्ध कराने और किराए पर ली गई बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ठेकेदारों के पास रहती है। राज्य की तरफ से संचालित परिवहन निकाय अपनी ओर से बसों के लिए उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। एमएसआरटीसी के चेयरमैन भरत गोगावाले ने मुंबई सेंट्रल स्थित राज्य परिवहन निकाय के मुख्यालय में अपनी बैठक की, जबकि बेस्ट के महाप्रबंधक अनिलकुमार डिग्गीकर ने कोलाबा स्थित नागरिक निकाय के मुख्यालय में निजी बस ऑपरेटरों से मुलाकात की।

**ड्राइवर के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य- महाप्रबंधक**

अनिलकुमार डिग्गीकर ने बताया कि बेस्ट को वेट लीज मॉडल के तहत बसें उपलब्ध कराने वाले सभी पांच निजी ऑपरेटरों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। कुर्ला दुर्घटना की जांच के लिए बेस्ट की तरफ से नियुक्त समिति के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'हम ड्राइवर प्रशिक्षण में एकरूपता ला रहे हैं, जिसमें ऑन-व्हील और सिमुलेशन प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं, और प्रत्येक ड्राइवर के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट (जो रक्त में अल्कोहल की मात्रा को मापता है) को भी अनिवार्य बनाया जा रहा है।'

उन्होंने कहा कि बैठक में उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि प्रत्येक ऑपरेटर अपने ड्राइवरों को किस तरह का प्रशिक्षण देता है और उनसे लिखित रूप में यह बताने को कहा कि वे अपने मौजूदा कार्यक्रम में क्या सुधार लाने जा रहे हैं। बेस्ट के महाप्रबंधक ने कहा कि उनके इनपुट का विश्लेषण किया जाएगा और फिर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी, और अगले सप्ताह एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निर्देश दिए जाएंगे।

**कुर्ला में बस हादसे की ये हो सकती है मुख्य वजह**

कुर्ला में हुए हादसे के बाद शुरुआत में संदेह था कि इलेक्ट्रिक वाहन बेस्ट बस के चालक संजय मोरे ने शराब पी रखी थी। यह भी संदेह था कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके कारण यह हाउसिंग सोसाइटी की दीवार से टकराने से पहले वाहनों और पैदल यात्रियों से टकराई। हालांकि, निरीक्षण के बाद आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि ब्रेक ठीक से काम कर रहे थे और हो सकता है कि दुर्घटना इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए ड्राइवर को उचित प्रशिक्षण न मिलने के कारण हुई हो। इस बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति में एमएसआरटीसी ने कहा कि निगम तीन सूत्री कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है - ड्राइवरों को प्रशिक्षण देना, उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत बनाना और अपने बेड़े में तकनीकी रूप से दोषरहित बसें शामिल करना।

**इस तरह से ड्राइवरों का चयन करता है बेस्ट**

राज्य की तरफ से संचालित निकाय ने कहा कि वर्तमान में वह अपने ड्राइवरों को 6 महीने का रिफ्रेशर प्रशिक्षण देता है और एक टेस्ट लेने के बाद उन्हें सेवा में शामिल करता है। इलेक्ट्रिक बस निर्माण कंपनियों ओलेक्ट्रा और ग्रीनसेल ने एमएसआरटीसी को एसी लग्जरी बसें आपूर्ति की हैं। निगम अपने लगभग 15,000 बसों के बेड़े की मदद से पूरे महाराष्ट्र में प्रतिदिन लगभग 55 लाख यात्रियों को परिवहन करता है, जिनमें निजी ऑपरेटरों के पट्टे पर लिए गए इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं।

# खून से क्यों लथपथ हो रही दिल्ली की सड़कें? सामने आई कई बड़ी वजह; जिम्मेदार अफसरों की नहीं टूट रही नींद

दिल्ली की सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों में लोगों की जान जा रही है। इन हादसों के पीछे लापरवाही से वाहन चलाना और सड़कों की खामियां हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली की किन सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

**नई दिल्ली।** राजधानी दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आए दिन हादसों में लोग अपनी जान गंवाते हैं। इन हादसों का मुख्य कारण लापरवाही से वाहन चलाना और सड़कों की डिजाइन के साथ तकनीकी खामियां हैं।

नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, मध्य व उत्तरी जिले की बात करें तो सबसे अधिक सड़क हादसे उत्तरी जिले में दर्ज किए गए हैं, इसमें भी आउटर रिंग रोड और रिंग रोड ब्लैक स्पाट घोषित हैं, जबकि एसपीएम मार्ग, रानी झांसी रोड, मध्य जिले के रिंग रोड, पटेल रोड, रानी झांसी, न्यू रोहतक रोड और नई दिल्ली जिले के मथुरा रोड व पंचकुइयां रोड दुर्घटना संभावित क्षेत्र में आते हैं।

आउटर रिंग रोड और रिंग रोड ब्लैक स्पाट घोषित होने के बावजूद प्रशासन ने इन सड़कों की खामियों को सुधारने में कोई खास ध्यान नहीं दिया। रात में अधिकतर सड़कों पर वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट के सहारे चलना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर लगी ज्यादातर लाइटें खराब पड़ी हैं और जो हैं भी वह पेड़ों में छिपी हुई हैं।

**सबसे अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र**

**आउटर रिंग रोड :** उत्तरी जिले की आउटर रिंग रोड सबसे खतरनाक रोड है। यहां पिछले वर्ष 95 सड़क हादसे हुए, जिसमें 30 घातक दुर्घटनाओं में 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह सड़क अति व्यस्ततम सड़क है, जहां रात-दिन लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। ब्लैक स्पाट (मजनू के टीला से वजीराबाद) घोषित होने के बावजूद रोड पर रात में अंधेरा छाया रहता है। चालक अपनी गाड़ी की हेड लाइट के सहारे चलते हैं। इसके अलावा न कोई रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही सही जगह पर संकेतक लगे हैं।

**उत्तरी जिले की रिंग रोड:** उत्तरी जिले की रिंग रोड (राजघाट से कश्मीरी गेट बस अड्डा) सबसे व्यस्त और खतरनाक ब्लैक स्पाट घोषित है। विगत वर्ष यहां 48 सड़क हादसे हुए, जिनमें 14 लोगों ने जान गंवाई। यहां बने ब्लैक स्पाट पर बिना संकेतक के अवैध कट के चलते सबसे अधिक हादसे हुए हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा रोड पर लगी हाई मास्ट लाइटें सड़कें के बजाये पेड़ों को जगमगा रही हैं।

**रानी झांसी रोड :** उत्तरी जिले की रानी झांसी रोड सदर बाजार को जोड़ती है। यह रोड पूरी तरह से अवैध पार्किंग व अतिक्रमण की चपेट में है। रात में यहां स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस रोड पर कोई संकेतक ठीक जगह पर नहीं लगे हैं और न ही लाइटिंग की व्यवस्था ठीक है। रात में सड़क पर अंधेरा छाया रहता है। अन्य सड़कों की अपेक्षा यहां

दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण जगह-जगह बने अवैध कट हैं।

**पटेल मार्ग:** सरदार पटेल मार्ग वीआइपी मार्गों में से एक है। यहां सड़कों की व्यवस्था सुचारू है, लेकिन फिर भी विगत वर्ष यहां 27 सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हुई। दुर्घटना संभावित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं।

**रानी झांसी रोड:** मध्य जिले की रानी झांसी रोड पर पिछले वर्ष 15 सड़क हादसे हुए, जिसमें छह लोगों की जाने गईं। इस रोड पर प्रशासन की अनदेखी लोगों की मौत का कारण बनी। यहां बने अवैध कट इस रोड पर होने वाले हादसों का प्रमुख कारण हैं। यहां पर्याप्त संकेतक तो लगे हैं। प्रशासन ने जिन स्थानों पर हादसे हुए उन्हें ब्लैक स्पाट तो घोषित कर दिया पर हादसे न हो उस पर कोई काम नहीं किया।

**मथुरा रोड :** नई दिल्ली जिले की मथुरा रोड पर प्रशासन द्वारा अव्यवस्थाओं को ठीक किया गया है। यहां प्रसिद्ध भारत मंडपम और सुप्रीम कोर्ट होने की वजह से काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। जगह-जगह बने कट को खत्म कर दिया गया है, फिर भी इस रोड पर पिछले वर्ष सात सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हुई थी। रोड पर लाइटों की भी व्यवस्था है और रिफ्लेक्टर भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं। वहीं संकेतक भी पर्याप्त जगह लगे हुए हैं।

**न्यू रोहतक रोड:** मध्य जिले की न्यू रोहतक रोड पर कमर्शियल वाहनों को अधिक आवाजाही रहती है। यहां विगत वर्ष हुए 27 सड़क हादसों में पांच लोगों की जान चलीं गई। वाहन चालकों की सुविधा के लिए लगाई गईं पोल लाइटें अधिकतर खराब पड़ी हैं। सड़कों पर अवैध तरीके से खड़े वाहनों ने रोड को घेरा हुआ है। इसके अलावा यहां बिना रोड के बीच में कट दिए हुए हैं, जिनसे हादसे की आशंका रहती है।

**एसपीएम मार्ग:** उत्तरी जिले का श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर विगत वर्ष 11 सड़क हादसे हुए, जिनमें पांच लोगों की मौत हुई। पुरानी दिल्ली स्टेशन होने के चलते यहां वाहनों की दिन-रात आवाजाही रहती है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के बावजूद सड़क अतिक्रमण की चपेट में हैं। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के चलते सड़क तंग भी हो गई है।

**मध्य जिले की रिंग रोड :** मध्य जिले की रिंग रोड सबसे घातक है। यहां विगत वर्ष 48 सड़क हादसे हुए, जिसमें 13 बड़े हादसों में 14 की जान गई। इस रोड पर तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं और यहां होने वाले हादसों का मुख्य कारण रात में छाया अंधेरा और रिफ्लेक्टर का न होना है। कई जगह पर बिना संकेतक के बने मोड़ हादसे का कारण बनते हैं।

**एमबी रोड:** दक्षिणी दिल्ली में महरौली से बदरपुर रोड इन दिनों घातक बनी हुई है। मेट्रो का काम चलने से सड़क पर वाहनों के चलने के लिए जगह कम बची है। जगह-जगह किनारों पर बैरिकेड लगे हैं, जिनके ओट से अचानक किसी के निकलने पर हादसे की आशंका बनी रहती है। सड़क कई जगह पर टूटी है और स्ट्रीट लाइटें भी ठीक नहीं हैं।

**पंचकुइयां रोड:** नई दिल्ली जिले की पंचकुइयां रोड भी अति व्यस्ततम रोड में से एक है। लेडी हार्डिंग अस्पताल और फर्नीचर मार्केट होने के चलते यहां वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। रोड पर विगत वर्ष पांच सड़क हादसों में तीन की जान गई है। इस रोड पर गड्ढे व अतिक्रमण हादसों का मुख्य कारण हैं।

**आउटर रिंग रोड:** ओखला एनएसआइसी से आइआइटी तक इस रोड पर पांच फ्लाईओवर हैं। सही दिशा सूचक बोर्ड के अभाव में जहां लोग रास्ता भटक जाते हैं, वहीं अचानक वाहन रोकने या मोड़ने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आउटर रिंग रोड पर भी कई जगह सड़कें टूटी हैं तो कहीं-कहीं स्ट्रीट लाइट गायब है। कुछ जगहों पर दिशा सूचक बोर्ड और स्ट्रीट लाइटें पेड़ों और झाड़ियों की ओट में छिप गए हैं। अंधेरा रहने पर इन जगहों पर अक्सर हादसे होते रहते हैं।

# खून की कमी होने पर इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज, कई बार एक्सपर्ट भी इग्नोर कर देते हैं

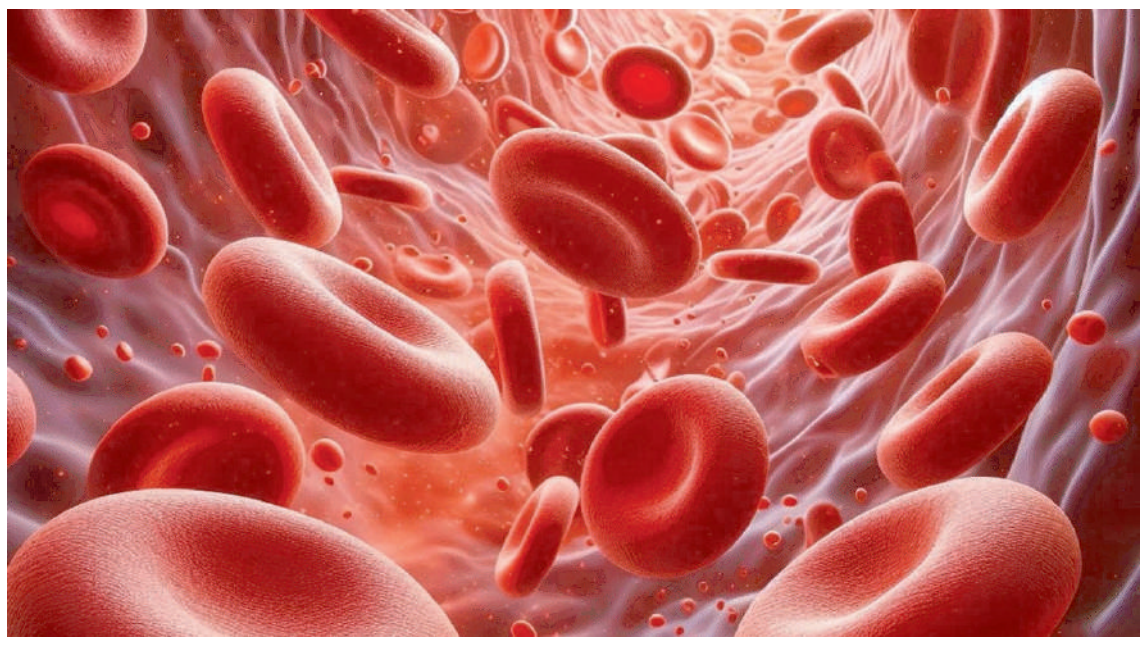

जब आपके शरीर में खून की कमी होती है, तो कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शरीर में एनीयिमा होने पर अक्सर कुछ लक्षण दिखते हैं, इन लक्षणों को दूर करने के लिए आप आयरन रिच फूड्स और विटामिन से भरपूर भोजन का सेवन करें।

जिन व्यक्ति के एनीमिया होने लगे तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए होता है। किसी भी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो शरीर में आयरन की कमी होने लगती है, जो कि हीमोग्लबिन को बनाने में मदद करता है। जब शरीर में खून की कमी दिखती है, तो कई लक्षण दिखाई देते हैं। थकान और कमजोरी के बावजूद भी कई लक्षण दिखते हैं। आइए आपको बताते हैं एनीमिया के छिपे लक्षण और दूर करने का तरीका

**न खाने वाली चीजों की क्रेविंग**

कई बार बच्चों से लेकर बड़े भी चॉक, बर्फ, धूल, गंदगी या मिट्टी जैसी न खाने वाली चीजें को मुंह में डालते हैं। इन नॉन फूड आइटम को खान क्रेविंग जरुर होती है, जो कि आयरन की कमी के लक्षण होते हैं। अगर आपको भी मिट्टी, धूल, चॉक और बर्फ जैसी चीजों को खाने की क्रेविंग होती है तो आयरन की कमी हो सकती है।

**रेस्टलेस लेग सिंड्रोम**

जो लोग लगातार पैर हिलाते रहते हैं और यह समस्या रात के समय ज्यादा बढ़ जाती है और रात को पैर स्थिर कर सोना आपका मुश्किल हो जाता है। इन लोगों के पैर में दर्द की शिकायत शुरु हो जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कारण लो आयरन लेवल या फिर आयरन की कमी हो सकती है।

**बालों का झड़ना**

अगर आपके बाल हद से ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर बाल बहुत पतले हो गए है। तो आपके शरीर में आयरन की कमी है।

**ठंड लगना**

यदि आपको नॉर्मल कमरे के तापमान में भी ठंड लगती है, तो आपके शरीर में आयरन की कमी है। इससे बेहतर है कि आप आयरन लेवल का टेस्ट कराएं।

**आयरन की कमी कैस दूर करें**

अगर आप आयरन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो रिच फूड्स खाने की सलाह मिलती है। हालांकि, आप आयरन और विटामिन रिच फूड्स का सेवन करें।

# Flipkart से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हो जाएं सतर्क, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा महंगा, कंपनी कर रही बड़ी प्लानिंग

दरअसल, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल आम सी हो गई है। कोई भी सामान खरीदना है तो उसके लिए हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग का ही सहारा लेता है। इसका कारण ये भी है कि अगर कोई सामान पसंद नहीं आता है तो उसे आसानी से वापस भी किया जा सकता है। लेकिन अब ऑर्डर को वापस करना या कैंसिल करना आसान नहीं होगा।

**नई दिल्ली।** ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जल्द ही ऑर्डर कैंसिल करने पर चार्ज वसूल करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल आम सी हो गई है। कोई भी सामान खरीदना है तो उसके लिए हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग का ही सहारा लेता है। इसका कारण ये भी है कि अगर कोई सामान पसंद नहीं आता है तो उसे आसानी से वापस भी किया जा सकता है। लेकिन अब ऑर्डर को वापस करना या कैंसिल करना आसान नहीं होगा। आपको ऑर्डर कैंसिल करना महंगा पड़ने वाला है।

सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जल्द ही कुछ ऑर्डर्स के लिए कैंसिलेशन चार्ज लगाने वाली है। फ्लिपकार्ट इसके लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव करने वाला है। हालांकि, ये कैंसिलेशन चार्ज किसी ऑर्डर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियम में ऑर्डर कैंसिल करने पर लगेगा। फिलहाल ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। हालांकि, कुछ दिन बाद उन्हें कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। ये चार्ज प्रोडक्ट के ऑर्डर वैल्यू पर निर्भर करेगा।

फ्लिपकार्ट ने आधिकारिक तौर पर कैंसिलेशन चार्ज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, सूत्रों की मानें तो कैंसिलेशन चार्ज के लिए एक टाइम लिमिट सेट की जाएगी। कंपनी फ्रॉड और विक्रेताओं को होने वाले नुकसान से बचने के लिए नई पॉलिसी लाने की प्लानिंग की। फ्लिपकार्ट के अलावा सिस्टर कंपनी Myntra पर ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करने पर भी ये चार्ज लगाया जा सकता है।

# शांति एवं शीतलता देने वाला कल्पवृक्ष है गीता

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों की दृष्टि का विस्तार होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब मैं अवतार लेता हूं. या प्रतिनिधि के रूप में किसी महापुरुष को भेजता हूं ताकि विश्व के अंदर शांति तथा धर्म का साम्राज्य स्थापित हो सके।

गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जिसकी हर साल जयंती मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। गीता को श्रीमद्भगवद्गीता और गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए उसे गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश में जीवन जीने, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व को समझाया गया है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है। गीता जयंती श्रीमद्भगवद्गीता के आगमन का शुभ दिन है। श्रीमद्भगवद्गीता दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता में श्रीकृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला, प्रबंधन और कर्म सब कुछ है। श्रीमद् भगवद् गीता स्वधर्म और कर्तव्य पथ का मार्ग प्रशस्त करती है। यह भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला संवाद है।

गीता कई सदियों पुराना ग्रंथ है, इसके हर शब्द में निहित तर्क, ज्ञान, जीवनदृष्टि एवं संसार को देखने एवं जीने का सार्थक नजरिया इसे एक कालातीत, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक मार्गदर्शक बनाता है। भगवद गीता के चिरस्थायी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे और क्यों की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह एक अलौकिक, अद्भुत एवं कालजयी रचना है, जो हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। इसके श्लोकों में हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने, जीवन की सच्चाई से परिचित होने और अंधविश्वास एवं झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में मदद मिल सकती है। गीता का ज्ञान हमारे संदेहों एवं शंकाओं को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सारांश रूप में देखा जाए तो गीता में आत्मा की नश्वरता (अमरता) 'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः' और कर्म (कर्त्तव्य पालन) 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' का उपदेश दिया गया है।

श्रीमद् भगवद गीता एक प्रमुख हिंदू धर्मग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। जिसमें दोहे/श्लोक हैं, इसके पाठ को संरचनात्मक रूप से 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। भगवद गीता को एक राजकुमार अर्जुन और भगवान के अवतार श्रीकृष्ण के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का यह संवाद सृष्टि की अनमोल धरोहर है। सुलह के कई प्रयास विफल होने के बाद, युद्ध अपरिहार्य था। आखिररकार युद्ध का दिन आ गया और सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने-सामने हुईं। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने विरोधी ताकतों पर अधिक बारीकी से नजर रखने के लिए अपने सारथि श्रीकृष्ण से रथ को युद्ध के मैदान के बीच में ले जाने के लिए कहा। श्रीकृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब कौरव सेना में अपने कुटुम्ब के लोग देखे तो वह निराश हो गए थे। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अपने कुटुम्ब के लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अर्जुन उनसे लड़ने के बारे में नैतिक दुविधा की स्थिति में होकर धनुष छोड़ देते और श्रीकृष्ण से मदद मांगते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुन को किंकर्तव्यविमुढ़, मोहग्रस्त एवं सांसारिकता में उलझा हुआ देखकर बोध देते हैं। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो सलाह, संदेश और उपदेश दिए, उसे अब भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। असल में गीता कोरा ग्रंथ नहीं, जीवन-दर्शन है। सदियों पहले दिये गये भगवान श्रीकृष्ण के गीता के उपदेश आज के समय में लोगों के जीवन की घोर निराशा, परेशानियों, सांसारिकता से निकालने का काम करते हैं। गीता को न सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी अपने जीवन में अपनाते हैं।

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों की दृष्टि का विस्तार होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब मैं अवतार लेता हूं. या प्रतिनिधि के रूप में किसी महापुरुष को भेजता हूं ताकि विश्व के अंदर शांति तथा धर्म का साम्राज्य स्थापित हो सके। गीता को श्रीमद्भगवद्गीता और गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है। गीता में श्रीकृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलने से

व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला, प्रबंधन और कर्म सब कुछ है। गीता के उपदेश के जरिए श्रीकृष्ण ने मनुष्य को अच्छे-बुरे और सही-गलत का फर्क बताया है। इस दिन गीता का पाठ करने से, उसके उपदेश पढ़ने से व्यक्ति को जीवन उजाला मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करने से आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपवास रखने से व्यक्ति का मन पवित्र होता है और शरीर स्वस्थ होता है। साथ ही व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है एवं जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है।

गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों की बौछार के आगे श्रीकृष्ण मौन थे। अर्जुन श्रीकृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे। युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे। लेकिन, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्रीकृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन, जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है, तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तब ही भगवान की कृपा मिलती है। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए, तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान एवं मोह को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो। सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'पार्थ! तुम केवल कर्म करो, फल की चिन्ता मत करो।' श्रीकृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिये नहीं, सम्पूर्ण मानव जाति के लिये था। कर्म के प्रति आसक्ति मनुष्य के अन्दर 'मैं' का भाव पैदा करती है। गीता मनुष्य को इस 'मैं' से मुक्त करके निष्काम कर्म का संदेश देती है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है, तो वह भी मुझे पा सकता है।

भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु-संन्यासियों के अन्तरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा-प्रवचनों से लेकर घर-घर तक जीवन-सुधार परक उपदेश, नीति-नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य निहित जान पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो, जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को, धर्म-अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो, तो वह जगह है-गीता। गीता रूपी ज्ञान-गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप-ताप-संताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है।गीता का गान करते-करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है, जहाँ उसे अलौकिक ज्ञान-प्रकाश, अपरिमित आनन्द प्राप्त होता है। वह न कोई शास्त्र है, न ग्रन्थ है। वह तो सबको शीतल छाया देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला, शंकाओं एवं आशंकाओं को दूर करने वाला कल्पवृक्ष है।

# बार-बार डोसा खाकर हो गए बोर, घर पर बनाएं हेल्दी और टेस्टी पोहा चीला, सब करेंगे आपकी तारीफ

रोजाना वही, बोरिंग नाश्ता करके आप पक गए होंगे। कुछ अलग और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी तलाश रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आएं कुछ मिनटों में तैयार होने वाला पोहा चीला, जिसे खाकर मजा आ जाएगा।

डेली एक जैसा नाश्ता खाकर आप भी थक गए होंगे और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस लेख में हम आपके लिए एक टेस्टी और हेल्दी पोहा चीला की रेसिपी लेकर आए है। इसे बनाना बेहद आसान है और कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

इस डिश में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पोहा चीला को हेल्दी नाश्ते की श्रेणी में रखा है। आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं।

**पोहा चीला बनाने के लिए सामग्री**

-1 कप पोहा (चपटा चावल)
-1/2 कप दही
-1 कप बारीक कटा हुआ प्याज
-1/2 कप कटी हुई गाजर
-1/4 कप धनिया पत्ती
-1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
-1 चम्मच कसा हुआ अदरक
-1 चम्मच हल्दी पाउडर
-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1 चम्मच धनिया पाउडर
-नमक स्वाद अनुसार
-1-2 चम्मच तेल (खाना पकाने के लिए)

**पोहा चीला बनाने की विधि**

- सबसे पहले पोहा को अच्छे से धोकर 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। फिर पानी निचोड़कर एक प्लेट में रख लें।

- इसके बाद कटोरे में भीगा हुआ पोहा, दही, बारीक कटा प्याज, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर सामग्री को अच्छे से मिला लें।

- अब आप नॉन-स्टिर पैन गरम करें और फिर थोड़ा सा तेल डालें। इसके बाद आप तैयार मिश्रण को तवे पर डालें और फिर एक चम्मच से इसे फैलाएं।

- इसके बाद जब यह सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकने दें। पक जाने पर इसे पैन से उतार लें और आपका गर्मा-गर्म पोहा चीला तैयार है। इसे आप चटनी या दही के साथ परोसें।

- स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें अपनी पसंद की अन्य सब्जियां, जैसे मटर या शिमला मिर्च मिला सकते हैं। कम कैलोरी वाले संस्करण के लिए, तेल के बजाय पानी का उपयोग करके चीला पकाएं।

# किचन में मौजूद इन 3 चीजों की मदद से बनाएं फेस पैक, चेहरे पर आएगा गजब का ग्लो

आज हम आपको एक ऐसे ब्यूटी हैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देगा। इस नुस्खे में इस्तेमाल की गई चीजें हमारे किचन में मौजूद होती हैं और यह हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है।

कैसा हो अगर आपकी स्किन का रंग साफ हो जाए और चेहरे पर कमाल का निखार आ जाए। जाहिर सी बात है कि आप खुशी से झूम उठेंगी। अधिकतर महिलाएं व लड़कियां ग्लोइंग स्किन पाने के लिए तरह-तरह के केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। जिसकी वजह से एलर्जी, स्किन के ड्राई होने और पिंपल बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देगा। इस नुस्खे में इस्तेमाल की गई चीजें हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही यह चीजें आपके किचन में मिल जाएंगी। तो आइए जानते हैं इन तीन चीजों के बारे में और इनसे फेस पैक बनाने के तरीके के बारे में

**इन 3 चीजों का करें इस्तेमाल**

बता दें कि हमारे किचन में कई ऐसे इंग्रीडिएंट्स मौजूद होते हैं, जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज हम आपको किचन में मौजूद उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका मिश्रण फेस पर अप्लाई करने से आपका चेहरा बेदाग निखार लाने का काम करेगा।

**फेस पैक सामग्री**

दूध- 1/2 कप
चावल का आटा- 1 चम्मच
एलोवेरा- 1 चम्मच

**ऐसे करें अप्लाई**

सबसे पहले एक छोटे से पैन में दूध और चावल के आटे को अच्छे से पका लें।

फिर जब तक यह गाढ़ा पेस्ट न हो जाए, तब तक इसको पकाएं।

जब चावल का आटा और दूध अच्छे से पक जाए तो इसको एक कटोरी में निकाल लें।

अब इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें।

फिर इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई करें और 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें।

सूखने के बाद नॉर्मल पानी से चेहरो धो लें और आप पाएंगे कि चेहरे की सारी गंदगी साफ हो गई और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी।

# गजब की गुणकारी है गाजर

1. गाजर का जूस शरीर में प्रोटीन की कमी को भी पूरा करने के साथ साथ शरीर को पर्याप्त मात्रा में केल्सियम भी प्रदान करके हड्डियों को मजबूती देता है।

2. गाजर का जूस बच्चे के गर्भावस्था के लिए खास तौर पर लाभकारी है। इसके उपयोग से बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आता है।

3. गाजर के जूस से मां के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है।

4. गाजर का जूस गर्भ में पल रहे बच्चे को इन्फेक्शंस से बचाए रखता है।

5. दिमाग को मजबूत बनाने के लिए गाजर का मुरब्बा प्रतिदिन सुबह लें।

6. निम्न रक्तचाप के रोगियों को गाजर के रस में शहद मिलाकर लेना चाहिए। रक्तचाप सामान्य होने लगेगा।

7. गाजर का रस, टमाटर का रस, संतरे का रस और चुकंदर का रस लगभग पच्चीस ग्राम की मात्रा में रोजाना दो माह तक लेने से चेहरे के मुंहासे, दाग, झाइयाँ आदि मिट जाते हैं।

# 16 विधायक गिरे धड़ाम! अब मंत्रियों की बारी? क्या टिकटों पर फिर कैंची चलाएगी आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी ने अभी तक 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है लेकिन बाकी 39 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। खास बात यह है कि आप ने अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल एक भी विधायक वाली सीट पर टिकट की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अपने कुछ मंत्रियों के टिकट भी काट सकती है।

**नईदिल्ली।** आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा अभी तक घोषित की गईं 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि कहीं आप अपने मंत्रियों के भी तो टिकट काटने नहीं जा रही है। आप ने अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल एक भी विधायक वाली सीट पर टिकट की घोषणा नहीं की है। आप ने 70 में से जिन 31 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें से 16 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें से कई अपने को मजबूत और शीर्ष नेतृत्व का करीबी मान रहे थे। अभी 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होना शेष है।

**विधायकों की हालत खराब**

आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर इस बार जितना सस्पेंस है, इतना कभी भी नहीं रहा है। मगर पार्टी कह रही है कि किसी प्रत्याशी के कहने पर कुछ नहीं होगा, जब जनता कहेगी तभी किसी विधायक को बेहतर माना जाएगा। ऐसे में इन विधायकों की हालत खराब है, जिनके अभी टिकट की घोषणा नहीं की गई है।

**एक सीट पर दो-दो दावेदार**

सूत्रों की मानें तो जिन सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, उनमें से अधिकतर सीटों पर अब दो-दो लोग ही आमने सामने हैं। दोनों की स्थिति को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले फिर से चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि दो बार में अगले नामों की घोषणा होगी।

**16 के टिकट कटने के बाद बाकी विधायकों में बेचैनी**

यहां बता दें कि 31 में से 16 विधायकों का टिकट कट जाने के बाद बचे हुए आप के विधायकों की बेचैनी ज्यादा बढ़ी है। किसी को नहीं पता है कि पार्टी में किस तरह का सर्वे हो रहा है और कब सर्वे करने वाली टीमें आती हैं और किस से बात करती हैं। ऐसे में बचे हुए विधायकों की नजर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगी है।

**विधायक अपना भविष्य तलाश रहे**

आप के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडेय का टिकट कटने से अन्य विधायकों की चिंता बढ़ी है, आप के पास कुल 59 विधायक हैं। उनमें से 28 पर अब फैसला होना है, जिन सीटों पर फैसला हो चुका है, उनमें से टिकट कटने वाले कई विधायक दूसरे दलों में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में आप के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान आप से इस्तीफा देकर मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।

**देखिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव (दूसरी लिस्ट)**

नरेला- दिनेश भारद्वाज
तिमारपुर- सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू
आदर्श नगर- मुकेश गोयल
मुंडका- जसबीर कराला
मंगोलपुरी- राकेश जाटव धर्मरक्षक
रोहिणी- प्रदीप मित्तल
चांदनी चौक- पुनर्दीप सिंह साहनी (साबी)
पटेल नगर- प्रवेश रतन
मादीपुर- राखी बिडलान
जनकपुरी- प्रवीण कुमार
बिजवासन- सुरेंद्र भारद्वाज
पालम- जोगिंदर सोलंकी
जंगपुरा- मनीष सिसौदिया
देवली- प्रेम कुमार चौहान
त्रिलोकपुरी- अंजना परचा

# दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली में बढ़े स्तर पर मतदाताओं की बढ़ोतरी में आ रही कमी और अधिक मात्रा में

सुषमा रानी

**नई दिल्ली,** दिल्ली निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित हुई जिसमें दिल्ली में लगातार वोट कम होने और अत्यधिक तादाद में वोट काटे जाने का मामला मुख्य मुद्दा रहा।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देशानुसार दिल्ली कांग्रेस ओर से वरिष्ठ नेता, पूर्व उपाध्यक्ष चतर सिंह और बूथ मैनेजमेंट कमेटी कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश गर्ग ने बैठ में उपस्थिति दर्ज की।

चतर सिंह ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि जब 2008-2013 के बीच दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 10.14 प्रतिशत बढ़कर 1,07,26,573 से 1,19,36,360 हो गई थी, 2013-15 में मतदाताओं की संख्या 1,33,13,295 के साथ 10.34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, 2015-20 के दौरान दिल्ली में मतदाता 10.03 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 1,47,97,990 हो गई। फिर 2020 से अक्टूबर, 2024 तक मतदाताओं की संख्या में सिर्फ 3.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी में कमी कैसे हुई और दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1,53,57,529 है।

चतर सिंह ने बताया कि पिछले 2008 से 2020 तक लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, तब 2020-2024 के दौरान वोट कम हुए है और कम भी बढ़े स्तर पर हुए है जिसका कारण मतदाताओं का नाम बढ़े स्तर पर काटा जा रहा है। 70 विधानसभाओं का पूरे डाटा का आंकलन करने के बाद सामने आया कि 17 विधानसभाओं में मतदाता घटे है और सिर्फ 11 विधानसभाओं में 10 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है और बाकी विधानसभाओं में औसत 10 प्रतिशत की जगह मात्र बहुत कम बढ़ोत्तरी हुई है।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो डाटा जारी किया उसमें समरी रिविजन के तहत नाम जोड़ने के 6 फार्म 2,10,574 भरे गए, नाम कटवाने के लिए 7 नम्बर फार्म 85,052 भरे गए और स्थानांतरण के लिए 8 नम्बर फार्म 1,19,987 भरे गए। अगर फार्म 6 की बढ़ोतरी में से फार्म 7 द्वारा कटौती को घटाकर देखें तो कुल बढ़ोत्तरी 1,25,522 है जो औसतन 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बहुत कम रहेगी। चतर सिंह ने कहा कि गैर तरीके से वोट कटौती या किसी पार्टी द्वारा बढ़े स्तर पर बड़ी-बड़ी सूची के साथ जो नाम काटे जा रहे है। जिसमें एक साजिश के तहत एक समुदाय के वोटों को कटवाने की कोशिश हो रही है, इसकी चुनाव आयोग जांच करें।

राजेश गर्ग ने प्रश्न उठाया कि बीएलओ के पास जो रजिस्टर है क्या उसमें वोट काटे जाने की जानकारी लिखी जाती है, क्या उस रजिस्टर में जिस घर का वोट कटा है उसके घरवालों के हस्ताक्षर है। इसकी व्यवस्था पूर्वक जांच होनी चाहिए। श्री गर्ग के प्रश्न के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी पार्टी के बीएलए स्वयं इसकी जांच कर सकते है, चुनाव आयोग या बीएलओ को कोई आपत्ति नही होगी।

# भाजपा के वोट काटने की साजिश के खिलाफ केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग से मिला "आप" प्रतिनिधिमंडल, तीन हजार पन्नों के सौंपे सबूत

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** 11 दिसंबर आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर वोट कटवाकर दिल्ली का चुनाव जीतने का षडयंत्र कर रही भाजपा का काला चिट्ठा केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने खोलकर रख दिया है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात कर तीन हजार पन्नों का सबूत सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में सीएम आतिशी, संजय सिंह, पंकज गुप्ता, जस्मीन शाह और रीना गुप्ता शामिल रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली में लोगों के वोट कटवाकर एक भारतीय नागरिक के रूप में मिले उनके अधिकारों को छीन रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभाओं में हजारों मतदाताओं के नाम काटने की एप्लिकेशन दी है और चुनाव आयोग उस पर चोरी-छिपे काम कर रहा है। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने का आश्वासन दिया है।

ज्यादातर झुग्गियों और कच्ची कालोनियों में रहने वाले गरीब, दलितों, पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

**कई विधानसभाओं में भाजपा के चंद कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है - केजरीवाल**

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में भाजपा के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को लिस्ट दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि जनकपुरी में 24 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 4874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में भाजपा के 15 वर्कर्स ने 2435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की कहानी बहुत ही अजीबो-गरीब है। बूथ नंबर 117 पर 1337 कुल वोट हैं। उन 1337 में 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने आवेदन किया है। यानि कि इन लोगों ने एक ही बूथ के 40 फीसदी वोट काटने के लिए आवेदन किया है। पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरि नगर में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में दो कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है।



***जिन लोगों ने गलत तरीके से वोट काटने के लिए आवेदन किया है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए - केजरीवाल***

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी मांग थी कि यह मांस डिलीशन बंद किया जाए। अभी-अभी चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन किया है, मांस डिलीशन बंद किया जाए। जिन-जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने हमें मोटे-मोटे तौर पर तीन-चार आश्वासन दिए हैं। पहला तो यह कि अब चुनाव से पहले कोई मांस डिलीशन नहीं किया जाएगा। दूसरा यह कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वह लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा, किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है, तो उस पर पहले फील्ड इनक्वायरी होगी। फील्ड इनक्वायरी में बीएलओ अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों को भी लेकर जाएंगे। तो सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ फील्ड इनक्वायरी होगी और उस इनक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। यह चुनाव आयोग का बहुत बड़ा आश्वासन है। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे।

***पांच से ज्यादा वोट काटने का आवेदन देने के मामले में एसडीएम को मौके पर जाकर जांच करनी होगी।**

**ऐसे समझें भाजपा की वोट कटवाने की साजिश***

- शाहदरा में भाजपा के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11008 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया है।
- जनकपुरी में भाजपा के 24 कार्यकर्ताओं ने 4874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है।
- तुगलकाबाद में भाजपा के 15 वर्कर्स ने 2435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है।
- तुगलकाबाद के पोलिंग बूथ नंबर 117 पर 1337 कुल वोट में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने आवेदन किया है।
- पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है।
- राजौरी गार्डन में भाजपा के 6 कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है।
- हरि नगर में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है।
- करावल नगर में दो कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट काटने का आवेदन किया है।
- मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है।

# गायकों की परफोरमेंस पर संगीत प्रेमी हुए मंत्रमुग्ध

सुषमा रानी

नई दिल्ली। फ्रेंक म्यूजिकल ग्रुप के तत्वावधान में ''पुकारता चला हूँ मैं सीजन-3'' का आयोजन लाजपत भवन के सभागार में किया गया। ग्रुप की फाऊंडर अन्नु फ्रेंक व डायरेक्टर इमेनुअल फ्रेंक की देखरेख में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में याकूब अख्तर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरक़त की। मेघा भारद्वाज के प्रबंधन और महेश ठाकुर के सहयोग से सजाए गए इस कार्यक्रम में मौहम्मद जुनैद खान व अभिलाषा शर्मा सेलीब्रिटी गेस्ट की हैसियत से मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, आबी प्रोडक्शन हाउस के सी-ई-ओ- योगेश मलिक, डॉक्टर रागिनी, फौजिया, फहीम खान, रॉय प्रोडक्शन हाऊस के डायरेक्टर अमित राय, संजय कुमार, गौरव व नवल घई आदि को भी खास मेहमान की हैसियत से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर याकूब अख्तर ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत ही काबिल सिंगरों को सुनने का अवसर आज मिला। कई संघर्षरत गायकों की परफोरमेंस भी यहां हमने सुनी, निःसंदेह आज का यह कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम साबित होगा। अन्नु फ्रेंक ने बताया कि हमने चुनिंदा गायकों को परफोर्म करने का अवसर दिया है ताकि यह कार्यक्रम उनको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सके। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने कहा कि यूं तो दिल्ली में प्रतिदिन अनेकों कार्यक्रम होते है लेकिन इस प्रोग्राम की एक विशेषता यह भी रही कि अनुशासन अंत तक बना रहा और कार्यक्रम को डिज़ाईन भी बेहतरीन तरीके से किया गया था। इस अवसर पर फिक्की की फ़ाइनेंस डायरेक्टर शबाना अज़ीम, टेलीविज़न एवं स्टेज एंकर उज़मा अंसारी, इवेंट ऑर्गनाइज़र व सिंगर हुमा ख़ान, राजा भार्गव, शायर सरफ़राज़ अहमद फ़राज़ देहलवी, अरविंद वत्स आदि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे !

# दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे: सर्दी की चेतावनी

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज
परिवहन विशेष

दिल्ली में सर्दियों का कहर बढ़ता जा रहा है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जो कि इस मौसम का पहला मामला है। मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए सर्दी की चेतावनी जारी की है।

**तापमान में गिरावट**

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को सफदरजंग में तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह पिछले कुछ वर्षों में सबसे कम तापमान है। इससे पहले, दिल्ली के कई हिस्सों में ठंड का असर महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब यह ठंड और भी बढ़ गई है।

इस ठंड के चलते लोगों को सर्दी से बचने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्म कपड़े पहनना और घर के अंदर हीटर का उपयोग करना आवश्यक है। इसके अलावा, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। अगले 48 घंटों में और भी ठंड बढ़ने की संभावना है। लोग इस समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और ठंड से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।

**सर्दी से बेघर लोगों की दयनीय स्थिति**

इस ठंड के मौसम में, विशेष रूप से बेघर लोग और निम्न आय वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग सड़कों पर या खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं, उनके लिए यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त कपड़े हैं और न ही कोई आश्रय स्थल। ऐसे में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं उठ रही हैं।

**सरकारी प्रयासों की कमी**

हालांकि, दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के दौरान आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों ही अपर्याप्त हैं। कई बेघर लोग इन आश्रयों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या वहां की सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में उन्हें ठंड से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

**स्वास्थ्य पर प्रभाव**

इस कड़ाके की ठंड से स्वास्थ्य समस्याओं का भी खतरा बढ़ गया है। निम्न आय वर्ग के लोग अक्सर सर्दी-जुकाम, निमोनिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जो उनकी जीवनशैली को और भी कठिन बना देती हैं।

दिल्लीवासियों के लिए यह सर्दी एक चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे इस ठंड के मौसम का सामना करने के लिए पूरी तैयारी करें। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

# दिल्ली ने किया 'द रैबिट हाउस' टीम का शानदार स्वागत उनके नेशनवाइड टूर के दौरान

सुषमा रानी

साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ₹द रैबिट हाउस₹ के प्रचार अभियान ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज की। अपनी दमदार कहानी और बेहतरीन कलाकारों के साथ, यह फिल्म पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। दिल्ली में हुई प्रचार ने दर्शकों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। यह फिल्म २० दिसंबर २०२४ को प्रदर्शित होने वाली है।

टीम ने दिल्ली प्रेस कांफ्रेंस मे बातचीत के दौरान फिल्म की कहानी और दृष्टिकोण को साझा किया। फिल्म के निर्माता कृष्णा पंधारे और सुनीता पंधारे, निर्देशक वैभव कुलकर्णी, और मुख्य कलाकार अमित रियान, पद्मनाभ गायकवाड़ और करिश्मा ने बताया कि क्यों ₹द रैबिट हाउस₹ केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित संवाद है, जो पूरे भारत के दर्शकों को जोड़ती है। फिल्म मे औरतों को लेकर डोमेस्टिक वॉयलेंस को भी बखूबी से दिखाया गया है।

टीम ने ये भी बताया कि ₹द रैबिट हाउस₹ एक पैन इंडिया फिल्म है जो विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ती है। निर्माता कृष्णा पंधारे ने कहा, "यह एक ऐसी कहानी है जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसकी विषयवस्तु—मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की अपेक्षाएं—सार्वभौमिक हैं। हमें विश्वास है कि यह फिल्म हर पृष्ठभूमि के दर्शकों को जोड़ पाएगी।"

निर्देशक वैभव कुलकर्णी ने कहा, ₹द रैबिट हाउस₹ एक ऐसा आईना है, जो समाज में अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्याओं को दिखाता है। हमने एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाने की कोशिश की है, जो केवल मनोरंजन न करे, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे।"



मुख्य अभिनेता अमित रियान, जो हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी भूमिका के बारे में बात की। वह फिल्म में एक ओसीडी (OCD) से जूझ रहे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह किरदार मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसने मुझे भावनात्मक स्तर पर बहुत गहराई में जाने का अवसर दिया। मुझे विश्वास है कि दर्शक इस संघर्ष और यात्रा से जुड़ पाएंगे।"

संगीत निर्देशक से अभिनेता बने पद्मनाभ गायकवाड़ ने इस नए अनुभव के बारे में कहा, "यह मेरे लिए एक नया और रोमांचक रचनात्मक अवसर था। यह यात्रा मेरे लिए बहुत संतोषजनक रही है।" अभिनेत्री करिश्मा ने कहा, "यह भूमिका मेरे लिए बहुत विशेष है।

# सफदरजंग अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट की हुई शुरुआत

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** सफदरजंग अस्पताल ने आज़ अपने लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट (एलएमयू) के उद्घाटन के साथ नवजात स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। भारत के चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को देखते हुए इस उपलब्धि का संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नवजात पोषण और मातृ-शिशु संबंध को प्राथमिकता देकर, अस्पताल व्यापक बाल चिकित्सा देखभाल में एक नया मानक स्थापित कर सकता है।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप बंसल ने दूध बैंकों के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया, उन्हें ₹समय की जरूरत₹ करार दिया और देश भर में हर नवजात इकाई में दूध बैंक स्थापित करने के भारत सरकार के आदेश के साथ संरेखित किया। यह एलएमयू सालाना 2000 नवजात शिशुओं को लाभान्वित करेगा जो सफदरजंग अस्पताल के मदर-एनआईसीयू में भर्ती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि स्तनपान भारत की अर्थव्यवस्था में 626 मिलियन अमरीकी डालर जोड़ सकता है और स्तनपान कराने वाले बच्चों के लिए तीन अतिरिक्त आईक्यू पॉइंट के साथ न्यूरोडेवलपमेंटल परिणामों में सुधार कर सकता है।

वीएमएमसी की प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना ने इस पहल की गहन क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि दूध बैंक की सुविधा सफदरजंग अस्पताल में नवजात मृत्यु दर और रुग्णता को काफी हद तक कम करेगी। बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. रतन गुप्ता ने लॉन्च के पीछे के सहयोगी प्रयास को स्वीकार किया, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अस्पताल प्रशासन के सहयोग को इसका श्रेय दिया।

मदर न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट (MNICU) की प्रभारी डॉ. सुगंधा आर्य ने बताया कि देश में प्रति वर्ष 27 मिलियन बच्चे जन्म लेते हैं, तथा प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 20 नवजात शिशुओं की मृत्यु दर चिंताजनक है। नव स्थापित 40 बिस्तरों वाली लेवल 3 मदर-NICU इकाई बाल चिकित्सा देखभाल के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जो माताओं और शिशुओं के लिए शून्य पृथक्करण नीति को बनाए रखते हुए व्यक्त माँ का अपना दूध और दाता मानव दूध दोनों प्रदान करती है। वर्तमान में मदर-NICU की देखरेख कर रही सहायक प्रोफेसर डॉ. रिया श्रीयान ने कहा कि माँ का दूध नवजात शिशुओं के लिए सबसे अच्छा भोजन है, और इससे हर छोटे और बीमार नवजात को माँ का अपना दूध या दाता मानव दूध उपलब्ध हो सकेगा। भारत में, अधिकांश स्तनपान प्रबंधन इकाइयाँ एक ही अस्पताल में जन्मे शिशुओं (इंट्राम्यूरल शिशुओं) के लिए काम कर रही हैं। यह केंद्र सरकार के अस्पतालों में रेफर किए गए शिशुओं के लिए पहला एलएमयू है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अस्पताल ने एमएनआईसीयू की स्थापना की है, जहाँ माताओं को नवजात शिशुओं के साथ भर्ती किया जाता है, जिसमें माँ और शिशु को अलग-अलग नहीं रखा जाता।

भारत की नवजात स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति सक्रिय और व्यापक प्रतिक्रिया, शिशु देखभाल और जीवित रहने की दरों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। साथ ही, भारत में वैश्विक समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, यह अनुमान लगाया गया है कि स्तनपान जैसे लागत प्रभावी और व्यवहार्य हस्तक्षेपों से मृत्यु दर में 3/4 की कमी संभव है। इसमें हर साल भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के 1,60,000 बच्चों की मृत्यु को रोकने की क्षमता है।

डॉ. संदीप बंसल ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में एलएमयू आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो दर्शाता है कि कैसे लक्षित स्वास्थ्य सेवा पहल सबसे कमजोर आबादी के जीवन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है।

# अलीगढ़-पलवल हाईवे चौड़ीकरण के लिए 21 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित, ₹600 करोड़ मुआवजे की घोषणा

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अलीगढ़-पलवल हाईवे के चौड़ीकरण की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत 21 गांवों की 160 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावित किसानों और निवासियों को ₹600 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा।

**₹2,500 करोड़ की परियोजना**

इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹2,500 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। इसमें से ₹1,500 करोड़ भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। अलीगढ़ से पलवल तक का यह मार्ग न केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ेगा बल्कि दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों तक यात्रा को सुगम बनाएगा।

**21 गांवों की भूमि का अधिग्रहण**

जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उनमें से 17 गांवों का मुआवजा अवार्ड घोषित किया जा चुका है। शेष चार गांवों का अवार्ड तैयार है, जबकि बाकी 10 गांवों के लिए प्रक्रिया जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांवों में शिविर लगाकर प्रभावित लोगों से संवाद शुरू कर दिया है।

**प्रभावित गांवों में नामित गांव**

चिह्नित गांवों में प्रमुख रूप से टप्पल और आसपास के इलाके शामिल हैं। यह मार्ग टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे और पलवल में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से जुड़ेगा। इससे आगरा, मथुरा, दिल्ली, एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, पलवल और गुरुग्राम तक पहुंच आसान होगी।

**किसानों और निवासियों को चुनौतियां**

हालांकि, यह परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है, लेकिन प्रभावित गांवों के निवासियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

**1. आजीविका पर असर:** भूमि अधिग्रहण से किसानों की कृषि भूमि खत्म हो जाएगी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी।

**2. आवासीय विस्थापन:** जिन क्षेत्रों में घर या व्यवसाय आते हैं, वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा।

**3. पर्यावरणीय प्रभाव:** परियोजना के कारण पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

**4. सामाजिक प्रभाव:** गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव आ सकता है।

**प्रशासन ने दिया आश्वासन**

प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास का भरोसा दिया है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शिविरों के माध्यम से संवाद किया जा रहा है।

**जनता की प्रतिक्रिया**

स्थानीय निवासियों ने मुआवजे की प्रक्रिया पर संतोष जताया है, लेकिन कई लोग भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी आजीविका और घर छिनने को लेकर चिंतित हैं।

यह परियोजना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रभाव स्थानीय निवासियों के जीवन पर लंबे समय तक रहेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए कितनी तेजी और संवेदनशीलता से काम करता है।

# नोएडा-ग्रेटर नोएडा में यातायात डायवर्जन: बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2024 के मद्देनजर

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने BAUMA CONEXPO INDIA 2024 कार्यक्रम के दौरान 10 से 14 दिसंबर तक यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस दौरान 14 मार्गों पर यातायात डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।

**प्रमुख डायवर्जन मार्ग:**

**1. चिल्ला रेड लाइट से ग्रेटर नोएडा की ओर:**

- सेक्टर-14A फ्लाईओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात डीएससी मार्ग होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**2. डीएनडी से ग्रेटर नोएडा की ओर:**

- रजनीगंधा चौक सेक्टर-16 की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात एमपी-01 मार्ग व डीएससी मार्ग होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**3. कालिंदी कुंज बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा की ओर:**

- महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात एमपी-03 मार्ग व डीएससी मार्ग होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**4. सेक्टर-37 से ग्रेटर नोएडा की ओर:**

- सेक्टर-44 गोलचक्कर से डबल सर्विस रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात डबल सर्विस रोड से होकर डीएससी मार्ग से अपने गंतव्य को जा सकेगा।

**5. आगरा से नोएडा की ओर:**

- जेवर टोल से आगे कस्बा जेवर की ओर उतरकर साबौता अंडरपास से खुर्जा बाईपास से जहांगीरपुर होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**6. परी चौक से नोएडा की ओर:**

- परी चौक से सूरजपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात सूरजपुर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होकर गंतव्य को जा सकेगा।

**7. सूरजपुर से परी चौक की ओर:**

- एलजी गोलचक्कर से 130 मीटर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात 130 मीटर रोड से होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**8. एलजी गोलचक्कर से एक्सपो मार्ट गोलचक्कर होकर नोएडा की ओर:**

- एलजी गोलचक्कर से यू-टर्न लेकर सूरजपुर, कुलेसरा, फेज-2, एनएसईजेड होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**9. पी-3 गोलचक्कर से परी चौक होकर सूरजपुर/ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर:**

- पी-3 गोलचक्कर से स्वर्ण नगरी गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात 130 मीटर रोड से होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**10. आगरा से नोएडा की ओर:**

- हिन्डन कट से सेक्टर-151 की ओर डबल सर्विस रोड होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**11. ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर:**

- चरखा गोलचक्कर से सेक्टर-94 की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 होकर गंतव्य को जा सकेगा।

**12. GIP की ओर से फिल्म सिटी फ्लाईओवर होकर DND की ओर:**

- फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न से डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात डीएससी मार्ग व एलिवेटेड मार्ग से गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**13. रजनीगंधा की ओर से DND फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर:**

- रजनीगंधा चौक से डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात DND मार्ग होकर न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गंतव्य की ओर जा सकेगा।

**14. गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर से सेक्टर-14A फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर:**

- गोलचक्कर चौक से डायवर्ट किया जाएगा।
- यह यातायात न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गंतव्य की ओर जा सकेगा।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे धैर्य रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन वाहनों को सुगम पारगमन दिया जाएगा। यातायात व्यवस्था सामान्य रहेगी, परंतु आवश्यकतानुसार अस्थायी परिवर्तन किए जा सकते हैं। BAUMA CONEXPO INDIA 2024 के दौरान नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे धैर्य रखें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।

# ग्रेटर नोएडा में रेलवे रूट के एलाइन्मेंट में बदलाव, अब भूमिगत की जगह सतह से गुजरेगा ट्रैक

Noida International Airport के लिए प्रस्तावित रेलवे रूट के एलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। तकनीकी कारणों से इसे भूमिगत न बनाकर भूमि की सतह पर बनाने का फैसला किया गया है। रेलवे ट्रैक एविएशन हब के सभी रनवे एक ओर रखते हुए दक्षिणी हिस्से से गुजरेगा। इससे यात्रियों और कार्गो ढुलाई में सुविधा होगी। यह दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेलवे रूट को वाया नोएडा एयरपोर्ट कनेक्ट करेगा।

**गाजियाबाद।** ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित रेलवे रूट के एलाइन्मेंट संरेखण में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद रेलवे ट्रैक एविएशन हब में प्रस्तावित सभी पांच रनवे एक ओर रखते हुए दक्षिणी हिस्से से गुजरेगा। इसे भूमिगत न बनाकर भूमि सतह पर बनाया जाएगा।

उत्तर मध्य रेलवे, यमुना प्राधिकरण व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) के बीच सहमति बन चुकी है। उत्तर मुख्य रेलवे ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सड़क के साथ रेलवे कनेक्टिविटी भी दी जाएगी।

**61 किमी होगी रेलवे ट्रैक की लंबाई**

दिल्ली मुंबई रेल रूट और दिल्ली हावड़ा रेल रूट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होकर जोड़ने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की थी। इसके तहत हरियाणा में पलवल के निकट रुंधी स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट होकर दिल्ली हावड़ा रूट पर चोला रेलवे स्टेशन के बीच नया रेल ट्रैक प्रस्तावित किया गया था।

एयरपोर्ट परिसर में इसे भूमिगत रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए भूमिगत की बजाए भूमि की सतह पर बनाने की सहमति बनी है।

**तकनीकी अड़चन के कारण एलाइन्मेंट में किया गया बदलाव**

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बनाया जाएगा। यह एयरपोर्ट के दोनों रनवे के बीच भूमिगत होगा। सड़क के साथ इसकी कनेक्टिविटी गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक प्रस्तावित नमो भारत रेल व दिल्ली वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल से भी होगी।

हाई स्पीड रेल के रूट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, लेकिन एक ही जगह पर कई रेलवे ट्रैक के मिलने के कारण होने वाली तकनीकी परेशानी को देखते हुए रुंधी चोला रेलवे रूट का एलाइन्मेंट बदलकर इसे भूमिगत की जगह सतह पर बनाने का फैसला किया गया है।

**टर्मिनल से करीब पांच किमी दूर से निकलेगा रेलवे ट्रैक**

रुंधी चोला रेलवे ट्रैक एयरपोर्ट के पहले चरण में बने टर्मिनल से करीब चार किमी की दूरी से होकर गुजरेगा। एविएशन हब के सभी रनवे इस ट्रैक के एक ओर होंगे। इसे एविएशन हब की दक्षिणी दिशा में बनाया जाएगा। इससे एक रनवे से दूसरे रनवे के बीच आवाजाही की कोई बाधा नहीं होगी। रेलवे स्टेशन से यात्रियों की टर्मिनल तक आवाजाही के लिए शटल बस आदि की सेवा होगी।

**यात्रियों के साथ कार्गो ढुलाई में मिलेगा लाभ**

रुंधी से चोला के बीच रेलवे ट्रैक की लंबाई करीब 61 किमी है। एलाइन्मेंट में बदलाव के बाद ट्रैक की लंबाई में भी बदलाव हो सकता है। दिल्ली मुंबई व दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट को नोएडा एयरपोर्ट होकर जोड़ने के कारण नए रेलवे रूट से यात्रियों के साथ साथ माल की ढुलाई आसान होगी। एयरपोर्ट व दोनों रेलवे रूट पर कार्गो की ढुलाई के लिए नया मार्ग तैयार हो जाएगा।

# गाजियाबाद में जल्द मिलेगा घर बनाने का मौका, हरनंदीपुरम योजना को लेकर आया ताजा अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

Harnandipuram Township in Ghaziabad गाजियाबाद में जल्द अपने सपनों का आशियाना बनाने का मौका मिलने जा रहा है। हरनंदीपुरम टाउनशिप नई आवासीय परियोजना में आवासीय व्यावसायिक और अतिरिक्त संपूर्ण योजना को समायोजित किया जाएगा। इस योजना के तहत बाहरी और अंदरूनी सड़कों की कनेक्टिविटी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इस योजना को सभी मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा।

**गाजियाबाद।** गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) सभागार में हरनंदीपुरम योजना को लेकर मंगलवार को वीसी अतुल वत्स की अध्यक्षता में तीन कंपनियों ने प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने योजना के क्षेत्रफल को देखते योजना को विकसित करने के लिए आवासीय, व्यावसायिक और अतिरिक्त संपूर्ण योजना को समायोजित करने के बारे में जानकारी दी।

**योजना को लेकर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर**

इस दौरान कंपनियों ने बताया कि हरनंदीपुरम योजना के तहत आवासीय, व्यावसायिक का विस्तार होने पर जल निकासी से लेकर ड्रेनेज सिस्टम और प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं। उन्होंने इस योजना के तहत बाहरी और अंदरूनी सड़कों की कनेक्टिविटी के बारे में भी विस्तार से बताते हुए कहा कि इसे सभी मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा।

**जीडीए सभागार में वीसी की अध्यक्षता में बताई विस्तार की योजनाएं**

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कंपनी की ओर से योजना को लेकर प्रजेंटेशन दे रहे प्रतिनिधियों से सवाल किए। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि अगर प्राधिकरण योजना के विस्तार में किसी तरह का बदलाव कराना चाहे तो वह इसके लिए बेहतर योजना तैयार करने में सक्षम हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार इन कंपनियों को फाइनेंशियल बिड में क्वालीफाई करने के लिए 70 अंक हासिल करना जरूरी है।

**क्वालीफाई करने पर खोला जाएगा फाइनेंशियल बिड**

तीनों कंपनियों के प्रजेंटेशन के बाद अब कमेटी द्वारा अंक दिए जाएंगे। क्वालीफाई करने पर फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा। फिर वर्क ऑर्डर जारी होगा। डीपीआर में प्रति हेक्टेयर के अनुसार ही कंपनी को प्राधिकरण की ओर से भुगतान किया जाएगा। प्रजेंटेशन के दौरान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक अशोक वाजपेयी आदि उपस्थित रहे।

**डीपीआर के लिए जीडीए नियुक्त करेगा सलाहाकार**

जीडीए हरनंदीपुरम टाउनशिप की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) प्रक्रिया जल्द आरंभ करेगा। उक्त जानकारी देते हुए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहाकार की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए गांव मथुरापुर, भोवापुर, भनैड़ा खुर्द, नगला फिरोजपुर, शमशेर, चंपतनगर, शाहपुर निज मोरटा क्षेत्र का सेटेलाइट और ड्रोन के जरिये रैपिड सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टाउनशिप विकसित करने के लिए चारदीवारी का चिह्नांकन कर लिया गया।

योजना में जमीन की कीमत तय करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शासन को भी योजना की विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। ताकि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फंडिंग का इंतजाम किया जा सके। जीडीए ने डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को आरंभ किया है। इसके बाद योजना की लागत का पता चल सकेगा। डीपीआर में सलाहकार का चयन क्वालिटी कम कास्ट वेस्ट सिस्टम से किया जाएगा।

# शाबाश ग्रामीण भारत !- ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 2023-24 में बढ़कर 77.5 पर्सेंट हुई-संसद में रिपोर्ट पेश

## समग्र शिक्षा अभियान,साक्षरता भारत, पढ़ना लिखना अभियान, उल्लास,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अनेक योजनाओं ने असर दिखाया। महिलाएं शिक्षा क्षेत्र के महत्व को समझ रही हैं जिनकी रोशनी से पूरा भारत रोशन हो रहा है

- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारतीय बौद्धिक क्षमता का डंका पूरी दुनियाँ में बज रहा है, यही कारण है कि दुनियाँ के विकसित देशों में अनेक भारतीय सीईओ नियुक्त हैं। बात यही तक नहीं रुकी, अब तो अनेक देशों का नेतृत्व मूल भारतीय कर रहे हैं व विपक्षी नेता से लेकर अनेक मुख्य पदों पर पदस्थ हैं, जिसका सटीक उदाहरण अभी 20 जनवरी 2025 से सत्ता पर काबिज़ होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मूल भारतीयों की नियुक्ति अपनी टीम में बड़े पदों पर लगातार की जा रही है जो रेखांकित करने वाली बात है। आज शिक्षा क्षेत्र पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया के ग्रामीण भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 2023-24 में बढ़कर 77.5 पर्सेंट हो गई है जो पिछले 2011 में 67.77 प्रतिशत थी, यह भी बताया गया कि एक ज़माना था जब महिलाओं की साक्षरता दर 14.5 पर्सेंट थी जो बाद में बढ़कर 57.93 पर्सेंट हो गई अब यह 77 पॉइंट 5 परसेंट हो गई है पुरुषों की भी साक्षरता दर बड़ी है जो पहले 77.5 पर्सेंट थी जो अब 84.5 पर्सेंट हो गई है इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल समग्र शिक्षा अभियान से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तक शामिल है जिसमें सबसे बड़े स्तर पर योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी है अब हम 100 पेर्सेंट रक्षक की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ेगा भारत तो विजन 2047 की डेडलाइन से पुरवाई भारत अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएगा क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान साक्षर भारत पढ़ना लिखना अभियान उल्लास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि अनेक योजनाओं ने असर दिखाया है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे शाबाश ग्रामीण भारत ! ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 2023 24 में 77.5 पेर्सेंट हुई संसद में मंत्रीक़े द्वारा जानकारी पेश हुई।

साथियों बात अगर हम संसद के शीत सत्र में 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा एक रिपोर्ट और जानकारी की करें तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है, सरकार की कामयाबी बताते हुए उन्होंने कहा, साल 2011 में साक्षरता दर 7 साल और उससे बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए 67.77 प्रतिशत थी, जोकि अब बढ़ कर साल 2023-24 में 77.5 प्रतिशत हो गई है ।भारत में काफी लंबे समय से महिलाओं को पढ़ाने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है और शिक्षा के महत्व को बताया गया है, इसी की वजह है कि अब वो बदलाव नजर आ रहा है, जिसके ख्वाब सालों पहले शायद सावित्री बाई फुले ने देखें थे, अब महिलाएं शिक्षा के महत्व को समझ रही हैं, जिसकी बदलती रोशनी के प्रकाश से पूरा भारत रोशन हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में इसमें उछाल आया है। एक समय में महिलाओं का साक्षरता दर 14.5 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जोकि फिर धीरे-धीरे 57.93 पेर्सेंट से 70.4 पेर्सेंट तक बढ़ गया है ।पुरुषों में भी साक्षरता दर बढ़ा है जोकि 77.15 पेर्सेंट से 84.7 पेर्सेंट तक इजाफा हुआ है साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए खास कर बालिग लोगों के बीच ग्रामीण साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है, जैसे, समग्र शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, पढ़ना लिखना अभियान और उल्लस-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन स्कीम ने पॉजीटिव रिजल्ट सामने रखे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर को बढ़ाया है ।नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने साक्षरता दर को बढ़ाने में अहम रोल निभाया है। अप्रैल 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, कार्यक्रम 15 साल से ज्यादा के लोगों को खास कर फोकस करता है। उल्लास स्कीम के तहत, हमने सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत किया है. साथ ही 1 करोड़ से अधीक लोग फाउंडेशनल लिटरेसी और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण के तहत पहले से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे बताया यह स्कीम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलाई जाती है. साथ ही मोबाइल एप की मदद से भी सीखना का ऑप्शन है जिस पर 26 भाषाएं उपलब्ध। इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की है। इस स्कीम के चलते 10.87 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्टर कराया और 4 लाख लोग इसके लिए उपस्थित हुए, साथ ही खुलासा किया कि बिहार ने अभी तकइस पहल को लागू नहीं किया है ।इतनी ग्रोथ हासिल करने के बाद भी ग्रामीण भारत में 100 प्रतिशत साक्षरा हासिल करना अभी भी एक चुनौती है ।उन्होंने शिक्षा के दायरे को बढ़ाने को लेकर कहा कि हालांकि, अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उल्लास जैसी पहल एक मजबूत संकेत दे रही है। इस स्कीम के तहत साक्षरता गेप को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है और खास कर महिलाओं को सशक्त बनाने और साक्षरता दर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पुरुष साक्षरता में भी सुधार हुआ है, जो समान अवधि में 77.15 प्रतिशत से बढ़कर 84.7 प्रतिशत हो गई है।

साथियों बातें अगर हम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में उल्लास प्रोग्राम नप 2020 के महत्वपूर्ण योगदान वह उसको जानने की करें तो, साक्षर भारत की ओर एक कदमउल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) के रूप में भी जाना जाता है, एक केंद्र प्रायोजित पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ संरेखित है। इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से आने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से चूक गए, ताकि उन्हें समाज में एकीकृत होने और राष्ट्र के विकास में योगदान करने में मदद मिल सके ।यह कार्यक्रम पढ़ने, लिखने और अंकगणित कौशल सहित कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर केंद्रित है, तथा विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जीवन कौशलों से समृद्ध करता है, तथा आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है ।स्वयंसेवा के माध्यम से क्रियान्वित, उल्लास सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना 'कर्तव्य बोध' को बढ़ावा देता है, तथा शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप/पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है ।शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्रों से उनका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है, जिससे निरंतर प्रगति होती है ।उल्लास योजना का उद्देश्य भारत को 'जन-जन साक्षर' बनाना है। यह योजना 'कर्तव्य बोध' (कर्तव्य) की भावना पर आधारित है और इसे स्वैच्छिक सेवा के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है ।कार्यान्वयन अवधिभारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2027 के दौरान के कार्यानवयन लिए योजना को मंजूरी दे दी है।

साथियों बात अगर हम सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा की करें तो, आजादी के पश्चात, भारत सरकार के समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार स्कूल जाने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूलभूत सेवाएं दी जाए। इस चुनौती की समाधान के लिए सरकार ने 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में संविधान संशोधन के माध्यम से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया और एन डी ए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का संचालन भी किया गया.हालांकि, जैसे ही भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, निस्संदेह उसे आधुनिक दुनिया की जरूरतों में शिक्षा और रोज़गार को बढ़ावा देने वाली एक सकारात्मक और समग्रनीति की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई जो लगभग 5 वर्षों तक चली और इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारक जैसे विद्यालय, शिक्षक, छात्र और गैरसरकारी संस्थाओं के विचारों को भी सुना गया जिसका परिणाम था की 2020 में एक व्यापक और समग्र राष्ट्रीय शिक्षा निति की संरचना की गई जिसका उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना हमारेपीएम के अथक प्रयासों से भारत में 34 वर्षों बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया, जिसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक प्राथमिक शिक्षा में 100पेर्सेंट सकल नामांकन अनुपातऔर उच्च शिक्षा में 50पेर्सेंट जीईआर हासिल किया जाए,इस नीति के माध्यम से शिक्षा में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निवेश के प्रावधान भी किये गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा सकल घरेलु उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा और छात्रों के विकास में उपयोग किया जायेगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि शाबाश ग्रामीण भारत !- ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 2023-24 में बढ़कर 77.5 पर्सेंट हुई-संसद में रिपोर्ट पेश समग्र शिक्षा अभियान,साक्षरता भारत, पढ़ना लिखना अभियान, उल्लास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अनेक योजनाओं ने असर दिखाया है ।महिलाएं शिक्षा क्षेत्र के महत्व को समझ रही हैं,जिनकी रोशनी से पूरा भारत रोशन हो रहा है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

# भारतीय प्रतिभा तंजानिया की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को बढ़ा रही है आगे

परिवहन विशेष न्यूज

तंजानिया का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2031 तक लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की राह पर है, जो 31% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जिसमें भारत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी भूमिकाओं के लिए एक प्रमुख प्रतिभा प्रदाता के रूप में उभर रहा है।

तंजानिया के ईवी निवेश इंजीनियरिंग, अनुसंधान, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध भारतीय पेशेवरों से बैटरी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना प्रबंधकों तक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने की उम्मीद है।

बैटरी डिजाइन, पावरट्रेन इंजीनियरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे प्रमुख कौशल की बहुत मांग है। ईवी सेक्टर के विकास ने दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण कौशल अंतर को उजागर किया है, जिसमें भारत को ईवी से संबंधित विशेषज्ञता में 40-45% की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

प्लग एन राइड के सीईओ ज़फ़र इकबाल का अनुमान है कि भारत को ईवी अपनाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक

2,00,000 कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी। इस अंतर को पाटने के लिए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को अपडेट करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय और तंजानिया कंपनियों के बीच साझेदारी इस कार्यबल परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। हाल के सहयोगों में तंजानिया में प्लग एन राइड का ईवी मोटरसाइकिल असेमब्लिंग प्लांट में ईवी के निर्माण के लिए उद्यम शामिल हैं। ये पहल न केवल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाती हैं बल्कि बैटरी रीसाइक्लिंग, स्मार्ट ग्रिड एकीकरण और संधारणीय गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में कैरियर के अवसर भी प्रदान करती हैं।

तंजानिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना स्थिरता और नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। भारतीय पेशेवर सिर्फ पदों को ही नहीं भर रहे हैं, बल्कि वे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को आकार दे रहे हैं। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि दोनों देश साझा विशेषज्ञता, उच्च वेतन और अधिक टिकाऊ भविष्य से लाभान्वित हों।

तंजानिया खुद को स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की गतिशीलता में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है, इसलिए इसके कार्यबल की गतिशीलता विकसित हो रही है। भारतीय पेशेवर, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, तंजानिया की ईवी महत्वाकांक्षाओं के लिए तेजी से केंद्रीय बन रहे हैं। 2029 तक ईवी बिक्री में 2.26 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित बाजार वॉल्यूम के साथ, यह वृद्धि दीर्घकालिक कैरियर के अवसर पैदा कर रही है जो प्रतिस्पर्धी वेतन, कौशल विकास और सीमा पार गतिशीलता प्रदान करते हैं।

# ईवी क्षेत्र को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, 2030 तक 40 अरब डॉलर का भारी निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

देश में इलेक्ट्रिक वाहन का चलन बढ़ रहा है। जिसके चलते अगले कुछ वर्षों में ईवी उद्योग में भारी निवेश की संभावना है। अधिकांश निवेश बैटरी बनाने में हो सकता है। सरकार ने 2030 तक कुल वाहनों में से 30 फीसदी का लक्ष्य रखा है, जबकि यह आंकड़ा फिलहाल 8 फीसदी के करीब है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ईवी वाहनों की बिक्री में सालाना औसतन 6 गुना की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म कोलियर्स के अनुसार भारत में ईवी और सहायक उद्योगों के विकास के लिए अगले 5 से 6 वर्षों में लगभग 40 बिलियन डॉलर के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें से सबसे अधिक 27 बिलियन डॉलर का निवेश लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में होना है, जो निवेश का 67 प्रतिशत है। इसके बाद ईवी और मूल उपकरण निर्माण के लिए 23 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 9 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

**इस समय देश में कुल वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 30 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए ईवी वाहनों की बिक्री में सालाना औसतन 6 गुना बढ़ोतरी की जरूरत है। इस साल 20 लाख ईवी वाहन बिकने की उम्मीद है, जबकि 2025 से 2030 के बीच सालाना औसतन 126 लाख ईवी वाहन बेचने की जरूरत है। अभी ईवी वाहनों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी तिपहिया वाहनों की है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 80 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए इन वाहनों की बिक्री में सालाना औसतन 6 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए।**

ईवी और सहायक उद्योगों के विकास के लिए 2030 तक 13,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही, ईवी के लिए चार्जिंग जैसे बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकता 2030 तक 4.5 मिलियन वर्ग फीट से अधिक की रियल एस्टेट मांग पैदा कर सकती है।

इस समय देश में कुल वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 30 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए ईवी वाहनों की बिक्री में सालाना औसतन 6 गुना बढ़ोतरी की जरूरत है। इस साल 20 लाख ईवी वाहन बिकने की उम्मीद है, जबकि 2025 से 2030 के बीच सालाना औसतन 126 लाख ईवी वाहन बेचने की जरूरत है। अभी ईवी वाहनों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी तिपहिया वाहनों की है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 80 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए इन वाहनों की बिक्री में सालाना औसतन 6 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए।

दोपहिया वाहनों की मौजूदा 6% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 80% करने के लिए 2025 से 30 के बीच 73 लाख वाहनों की औसत वार्षिक बिक्री के साथ 6 गुना वृद्धि की आवश्यकता है। इसी तरह, इस अवधि के दौरान चार पहिया वाहनों की मौजूदा 3% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 30% करने के लिए 9 गुना वृद्धि के साथ सालाना औसतन 9 लाख ईवी बेचे जाने चाहिए, जबकि भारी वाहनों की मौजूदा 3% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 40% करने के लिए इस अवधि के दौरान 4 गुना वार्षिक वृद्धि के साथ हर साल औसतन 40 हजार भारी ईवी बेचे जाने चाहिए।

कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक ने कहा कि हाल के वर्षों में ईवी की मांग बढ़ी है, लेकिन 2030 तक 30 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य एक कठिन काम लगता है। ईवी को तेजी से अपनाने में मांग और आपूर्ति प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। उत्पादन लागत में कमी और उनकी कीमतों में सुधार से ईवी की बिक्री कई गुना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त उच्च क्षमता वाली मूल उपकरण निर्माण इकाइयाँ और लिथियम-आयन बैटरी वेरिएंट का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राथमिकता होनी चाहिए।

# स्विच मोबिलिटी ने भारत और यूरोप के लिए पेश की नई इलेक्ट्रिक बसें ईआईवी12 और ई1

परिवहन विशेष न्यूज

अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी और हिंदुजा समूह का हिस्सा स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने भारतीय बाजार के लिए ईआईवी12 और यूरोप के लिए डिज़ाइन की गई ई1 नामक दो नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें पेश की हैं। ये बसें भारत, यूरोप और जीसीसी क्षेत्रों में शहरी गतिशीलता समाधानों को मजबूत करने के कंपनी के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

स्विच ईआईवी12 एक लो-फ्लोर सिटी बस है, जिसे खास तौर पर भारत में शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें चेसिस-माउंटेड बैटरी है जिसकी स्केलेबल बैटरी क्षमता 400 किलो वाट से ज़्यादा है, जो इसे भारत में अपनी तरह की पहली लो-फ्लोर सिटी बस बनाती है। ईआईवी12 प्लेटफ़ॉर्म को भारत के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हिंदुजा समूह के चेयरमैन अशोक पी. हिंदुजा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और उद्योग जगत के नेताओं की मौजूदगी में लॉन्च किया।

इसके अलावा यूरोपीय बाजार के लिए तैयार किए गए स्विच ई1 को भी वर्चुअली लॉन्च किया गया। दोनों मॉडल में समान डिजाइन दर्शन और ईवी आर्किटेक्चर है।

स्विचईआईवी12 को शहरी आवागमन के लिए भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जो प्रदर्शन, सुरक्षा, विश्वसनीयता और यात्री आराम में वैश्विक मानकों की पेशकश करता है। 39 यात्रियों के बैठने की

जगह के साथ, ईआईवी12 का उद्देश्य बेड़े संचालकों के लिए परिचालन दक्षता को अधिकतम करना है।

हिंदुजा समूह के चेयरमैन अशोक पी. हिंदुजा ने कहा, ₹ये बसें प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं - भारत में निर्मित, भारत और दुनिया के लिए। स्विच मोबिलिटी भारत में बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण अत्याधुनिक तकनीक और शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ नवाचार करना जारी रखती है।"

स्विच मोबिलिटी के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने इस बात पर जोर दिया कि, ₹स्विच ईआईवी12 और ई1 का यूरोप के लिए लॉन्च होना हिंदुजा समूह और अशोक लीलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो टिकाऊ गतिशीलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। स्विच हमारी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित कर रहा है।"

स्विच मोबिलिटी के सीईओ महेश बाबू ने कहा, ₹हम भारत और यूरोप के लिए डिज़ाइन किए गए दो नए उत्पादों को पेश करने के लिए उत्साहित हैं, जो हमारे वैश्विक ईवी आर्किटेक्चर पर निर्मित हैं। स्विच ईआईवी12 को पहले ही 1,800 से अधिक ऑर्डर मिल चुके हैं, जो हमारे टिकाऊ शहरी परिवहन विज़न में बाज़ार के भरोसे को दर्शाता है।"

भारतीय इलेक्ट्रिक सिटी बस बाजार में 2030 तक 21% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें ईवी प्रवेश 70% तक पहुँचने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक सिटी बसों का कुल बेड़ा 2030 तक 70,000 इकाइयों को पार करने का अनुमान है।

स्विच ईआईवी12 यात्री आराम, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित करता है। घुटने टेकने की व्यवस्था के साथ इसकी लो-फ्लोर एंट्री आसान पहुँच सुनिश्चित करती है, जबकि स्वचालित व्हीलचेयर रैंप और समर्पित स्थान इसे विकलांग यात्रियों के लिए सुलभ बनाते हैं। बस में सुरक्षा के लिए पाँच सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं के लिए पाँच समर्पित सीटें और एक पैनोरमिक ग्लास क्षेत्र है जो दृश्यता और आंतरिक प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाता है।

मालिकाना स्विच आईओएन टेलीमैटिक्स सिस्टम द्वारा संचालित, ईआईवी12 वास्तविक समय वाहन स्वास्थ्य निगरानी, एकीकृत बेड़े प्रबंधन, और त्वरित रिचार्जिंग और अनुकूलित डिपो स्पेस उपयोग के लिए एक कुशल रियर-एंड डुअल-गन चार्जिंग इंटरफ़ेस प्रदान करता है। इसकी आईपी67 रेटेड बैटरी चुनौतीपूर्ण सड़क स्थितियों में विश्वसनीय प्रदर्शन की अनुमति देती है।

स्विच ई1 को खास तौर पर यूरोपीय बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हल्के मोनोकोक निर्माण और इन-व्हील मोटर्स की सुविधा है। यह एक फ्लैट गैंगवे लेआउट, ट्रिपल-डोर कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है, और स्टैंडियों सहित 93 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। ई1 का उद्देश्य शहरी पारगमन प्रणालियों में यात्री-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करना है।

# महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने वाणिज्यिक ईवी के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस लॉन्च करने के लिए विद्युत के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने विद्युत के साथ मिलकर अपने 4 व्हीलर और 3 व्हीलर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस पहल की घोषणा की है।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस कार्यक्रम 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाले भुगतान-योग्य किराये का विकल्प प्रदान करता है, जो इन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की प्रारंभिक लागत को 40% तक कम करने में मदद करता है।

बेंगलुरु स्थित फुल-स्टैक ईवी स्टार्टअप विद्युत ग्राहकों को बैटरी खरीदने के बजाय उसे किराए पर लेने का विकल्प देगा। इससे ग्राहकों को 4 व्हीलर महिंद्रा जिओ, ज़ोर ग्रैंड और 3 व्हीलर ट्रियो प्लस जैसी ईवी खरीदने की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल के अंतर्गत, वाहन मालिकों को किराये के कार्यक्रम को जारी रखने या वित्तपोषण अवधि के अंत में बैटरी खरीदने की सुविधा मिलती है।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा, ₹बैटरी-एज़-ए-सर्विस विकल्प के माध्यम से, हमारा लक्ष्य प्रारंभिक लागत को कम करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र में ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिले।"

विद्युत के सह-संस्थापक, ज़ीतिज कोठी ने इस बात पर जोर दिया, ₹हमारा दृष्टिकोण बैटरी को एक सेवा के रूप में मानने पर केंद्रित है, जिससे ग्राहकों को केवल बैटरी के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके और साथ ही ईवी स्वामित्व का वित्तीय बोझ कम हो सके।₹ महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है, जो ट्रिओ, ज़ोर ग्रैंड और ई-अल्फा वाहनों सहित इलेक्ट्रिक, पेट्रोल,

# महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने वाणिज्यिक ईवी के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस लॉन्च करने के लिए

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने वाणिज्यिक ईवी के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस लॉन्च करने के लिए विद्युत के साथ की साझेदारी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने विद्युत के साथ मिलकर अपने 4 व्हीलर और 3 व्हीलर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस पहल की घोषणा की है। बैटरी-एज़-ए-सर्विस कार्यक्रम 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाले भुगतान-योग्य किराये का विकल्प प्रदान करता है, जो इन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की प्रारंभिक लागत को 40% तक कम करने में मदद करता है। बेंगलुरु स्थित फुल-स्टैक ईवी स्टार्टअप विद्युत ग्राहकों को बैटरी खरीदने के बजाय उसे किराए पर लेने का विकल्प देगा। इससे ग्राहकों को 4 व्हीलर महिंद्रा जिओ, ज़ोर ग्रैंड और 3 व्हीलर ट्रियो प्लस जैसी ईवी खरीदने की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी। बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल के अंतर्गत, वाहन मालिकों को किराये के कार्यक्रम को जारी रखने या वित्तपोषण अवधि के अंत में बैटरी खरीदने की सुविधा मिलती है। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा, ₹बैटरी-एज़-ए-सर्विस विकल्प के माध्यम से, हमारा लक्ष्य प्रारंभिक लागत को कम करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र में ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिले।₹ विद्युत के सह-संस्थापक, ज़ीतिज कोठी ने इस बात पर जोर दिया, ₹हमारा दृष्टिकोण बैटरी को एक सेवा के रूप में मानने पर केंद्रित है, जिससे ग्राहकों को केवल बैटरी के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके और साथ ही ईवी स्वामित्व का वित्तीय बोझ कम हो सके।₹ महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है, जो ट्रिओ, ज़ोर ग्रैंड और ई-अल्फा वाहनों सहित इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल लास्ट-माइल मोबिलिटी समाधानों की विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।बैटरी-एज़-ए-सर्विस एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जो इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को बैटरी को सीधे खरीदने के बजाय वाहन से अलग से किराए पर लेने की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण ने शुरुआती लागत को कम करने, सामर्थ्य को बढ़ाने और व्यापक ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में गति प्राप्त की है।बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल में बैटरी के स्वामित्व को वाहन से अलग रखा जाता है, जिससे ग्राहक बैटरी के उपयोग के लिए किलोमीटर की संख्या के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। इससे ईवी खरीदने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश कम हो जाता है, जिससे यह वाणिज्यिक और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। किराये की लागत आमतौर पर भुगतान-प्रति-उपयोग शुल्क के रूप में संरचित होती है, जो अक्सर यात्रा की गई दूरी पर आधारित होती है, जिससे अक्सर ईवी खरीदने के साथ आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलती है।बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल वाणिज्यिक बेड़े के लिए परिचालन दक्षता में सुधार कर सकते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में, जहां वाहनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। बैटरी-एज़-ए-सर्विस की पेशकश

# सफल लोग अलग तरह से काम करते हैं

विजय गर्ग

सबसे अधिक ध्यान देने योग्य अंतरों में से एक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। सफल लोग आजीवन सीखने वाले होते हैं जो कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होते। वे ज्ञान को एक गतिशील संसाधन के रूप में देखते हैं, जो लगातार अपने क्षितिज का विस्तार करने और अपने कौशल को निखारने की कोशिश करते हैं। निरंतर सीखने की यह प्रतिबद्धता उन्हें लगातार बदलती दुनिया में अनुकूलनीय बनाए रखती है। चाहे पढ़ने के माध्यम से, सलाह लेने के माध्यम से, या नए विचारों के साथ प्रयोग करके, वे सुनिश्चित करते हैं कि वे प्रासंगिक बने रहें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें।

सफलता को अक्सर प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अवसर के संयोजन के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये कारक निर्विवाद रूप से एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से यह नहीं समझाते हैं कि क्यों कुछ व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल करते हैं जबकि समान क्षमताओं और परिस्थितियों वाले अन्य लोग असफल हो जाते हैं। विशिष्ट कारक अक्सर इस बात में निहित होता है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं। वे केवल पारंपरिक रास्तों का अनुसरण नहीं करते हैं; वे एक अनोखी मानसिकता और सोच-समझकर की गई आदतों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। ये अंतर, सूक्ष्म लेकिन गहन, उनकी सफलता की रीढ़ बनते हैं और उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। उनके दृष्टिकोण के मूल में उद्देश्य की अविश्वसनीय स्पष्टता है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और यह क्यों मायने रखता है। यह स्पष्टता एक कम्पास के रूप में कार्य करती है, जो यात्रा जटिल और अनिश्चित होने पर भी उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। उनके लक्ष्य अस्पष्ट महत्वाकांक्षाएं नहीं बल्कि सटीक उद्देश्य हैं जो कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित हैं। अपने वांछित परिणामों पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने की यह क्षमता उन्हें विकर्षणों से बचने और गति बनाए रखने में मदद करती है। वे समझते हैं कि सफलता के लिए उनके दृष्टिकोण के प्रति एकनिष्ठ समर्पण की आवश्यकता होती है, और वे इसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की संरचना करने के इच्छुक होते हैं। एक और परिभाषित गुण चुनौतियों को बाधाओं के बजाय अवसरों के रूप में देखने की उनकी क्षमता है। अधिकांश लोगों के लिए, विफलता एक बाधा है, पीछे हटने या हार मानने का एक कारण है। सफल व्यक्तियों के लिए, विफलता प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है - मूल्यवान सबक का एक स्रोत जो उन्हें आगे बढ़ाता है। परिप्रेक्ष्य में यह अंतर लचीलापन पैदा करता है, एक ऐसा गुण जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। वे असफलता से नहीं डरते क्योंकि वे इसे एक बाधा के बजाय एक कदम के रूप में देखते हैं। यह मानसिकता, परिकलित जोखिम लेने की उनकी इच्छा के साथ मिलकर, उन्हें नए रास्ते तलाशने और वहां कुछ नया करने की अनुमति देती है जहां अन्य लोग झिझकते हैं। सफल लोगों के लिए समय लापरवाही से खर्च किया जाने वाला संसाधन नहीं है। वे इसे अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं, यह समझते हुए कि वे अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, अंततः उनकी उपलब्धियों का दायरा निर्धारित होता है। कई लोगों के विपरीत, जो ध्यान भटकाने वाले या काम टालने वाले होते हैं, सफल व्यक्ति जानबूझकर समय प्रबंधन का अभ्यास करते हैं। वे उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो

उनके लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं और उन गतिविधियों से बचते हैं जो उनके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। यह अनुशासित दृष्टिकोण उन्हें अत्यधिक काम के जाल में फंसे बिना उत्पादकता को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। उन्हें एक संतुलन मिलता है जो उन्हें अपनी भलाई और रिश्तों को बनाए रखते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति देता है। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य अंतरों में से एक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। सफल लोग आजीवन सीखने वाले होते हैं जो कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होते। वे ज्ञान को एक गतिशील संसाधन के रूप में देखते हैं, जो लगातार अपने क्षितिज का विस्तार करने और अपने कौशल को निखारने की कोशिश करते हैं। निरंतर सीखने की यह प्रतिबद्धता उन्हें लगातार बदलती दुनिया में अनुकूलनीय बनाए रखती है। चाहे पढ़ने के माध्यम से, सलाह लेने के माध्यम से, या नए विचारों के साथ प्रयोग करके, वे सुनिश्चित करते हैं कि वे प्रासंगिक बने रहें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। उनकी जिज्ञासा उनके विकास को बढ़ावा देती है, उन्हें अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं से परे अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। सार्थक रिश्तों के निर्माण और पोषण पर उनका ध्यान उनकी सफलता का एक और निर्णायक पहलू है। अकेली प्रतिभा के मिथक के विपरीत, अधिकांश सफल लोग सहयोग और समुदाय की शक्ति को पहचानते हैं। वे अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। इनरिश्ते सतही नेटवर्किंग पर नहीं बल्कि विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित वास्तविक संबंधों पर बनते हैं। ऐसा नेटवर्क न केवल व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है बल्कि कठिन समय के दौरान ताकत के स्रोत के रूप में भी काम करता है। प्रभावी ढंग से सहयोग करने की क्षमता उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने और ऐसे लक्ष्य हासिल करने की अनुमति देती है जो अकेले असंभव होंगे। निरंतर सफलता प्राप्त करने वालों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण एक प्राथमिकता है। वे मानते हैं कि उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है। परिणामस्वरूप, वे नियमित व्यायाम, सचेतनता और संतुलित आहार जैसी प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। ये आदतें केवल शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के बारे में नहीं हैं; वे फोकस भी बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और भावनात्मक लचीलेपन में सुधार करते हैं। सफल व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को एक अपरिहार्य निवेश मानते हैं, यह समझते हुए कि यह उनके जीवन के अन्य सभी पहलुओं को रेखांकित करता है। भलाई पर यह जोर उन्हें निरंतरता के साथ अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्पष्टता बनाए रखने की अनुमति देता है। शायद सफल व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण अपने काम के प्रति उनका जुनून है। उन लोगों के विपरीत जो अपनी नौकरी को केवल दायित्वों के रूप में देखते हैं, वे अपनी गतिविधियों को अपनी पहचान और उद्देश्य के विस्तार के रूप में देखते हैं। यह आंतरिक प्रेरणा उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, अक्सर अपेक्षा या आवश्यकता से आगे बढ़कर। जुनून उनके प्रयासों को खुशी और तृप्ति की भावना से भर देता है, जिससे सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य भी सार्थक हो जाते हैं। यह उनके काम के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जो तात्कालिक पुरस्कारों के अभाव में भी लंबे समय तक उनकी प्रतिबद्धता को कायम रखता है। अनुकूलनशीलता सफल लोगों की एक और पहचान है। वे अनिश्चितता में पनपते हैं क्योंकि जब परिस्थितियां मांग करती हैं तो वे आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। इस लचीलेपन का मतलब दिशा की कमी नहीं है; बल्कि, यह अपने अंतिम उद्देश्यों के प्रति सच्चे रहते हुए अपने तरीकों को पुनः अंशांकित करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। वे समझते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है और कठोरता के कारण अक्सर अवसर चूक जाते हैं। अनुकूलनशीलता को अपनाकर, वे संभावित असफलताओं को विकास और नवाचार के मंच में बदल देते हैं। उनकी विकसित होने की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि वे लगातार बदलती दुनिया में प्रतिस्पर्धी और प्रभावी बने रहें। हालाँकि उनकी उपलब्धियों का अक्सर जश्न मनाया जाता है, सफल लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं और व्यापक तस्वीर के प्रति जागरूक रहते हैं। कृतज्ञता उनके जीवन में बार-बार आने वाला विषय है। वे अपनी यात्रा में दूसरों- गुरुओं, साथियों और यहां तक कि प्रतिस्पर्धियों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। कृतज्ञता की यह भावना विनम्रता और संतुष्टि को बढ़ावा देती है, और उन्हें अधिक की अंतहीन खोज में फंसने से रोकती है। यह उन्हें सकारात्मक परिवर्तन लाने के साधन के रूप में अपनी सफलता का उपयोग करके वापस देने के लिए भी प्रेरित करता है। चाहे सलाह, परोपकार, या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, वे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे योगदान करने के तरीके ढूंढते हैं।

संक्षेप में, सफल लोग जो अलग ढंग से करते हैं वह कोई गुप्त सूत्र या असाधारण प्रतिभा नहीं है। यह आदतों, मानसिकताओं और प्रथाओं का एक संयोजन है जो उन्हें अपनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है। उनके उद्देश्य की स्पष्टता, विफलता के सामने लचीलापन, समय का अनुशासित उपयोग, विकास के प्रति प्रतिबद्धता, रिश्तों पर जोर, स्वास्थ्य पर ध्यान, अपने काम के प्रति जुनून, अनुकूलनशीलता और कृतज्ञता उनकी सफलता की नींव बनाते हैं। ये लक्षण जन्मजात नहीं हैं; उन्हें जानबूझकर किए गए प्रयास और निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाता है। सबक यह है कि सफलता कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है। जबकि वेंरास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, उपलब्धि हासिल करने वाले सिद्धांत सार्वभौमिक बने रहते हैं। इन आदतों को समझकर और दैनिक जीवन में शामिल करके, कोई भी अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकता है और जो संभव है उसे फिर से परिभाषित कर सकता है। सफलता, जैसा कि इसे हासिल करने वालों ने प्रदर्शित किया है, मंजिल के बारे में कम और यात्रा के बारे में अधिक है - जो उद्देश्य, दृढ़ता और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित है।

**सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब**

## कहानी

### ईश्वर में विश्वास

विजय गर्ग

एक सन्त कुएं पर स्वयं को लटका कर ध्यान किया करते थे और कहते थे, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी, मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे।

उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूँ।

वह रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा।

.

जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दिए।

तब व्यक्ति ने पूछा- आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आये, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं।

कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उसे मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है।

तुझे खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं आ गया।

आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगें। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी।

प्रश्न केवल इतना है आप उन पर कितना विश्वास करते हैं।

ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। शरीररूपी यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को, वे अपनी माया से घुमाते रहते हैं, इसे सदैव याद रखें और बुद्धि में धारण करने के साथ व्यवहार में भी धारण करें।

# डिजिटल गिरफ्तारी और उसका प्रभाव : विजय गर्ग

एक आधुनिक विचार है जो ऐसी दुनिया में उभरा है जहां प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। डिजिटल गिरफ्तारी से तात्पर्य व्यक्तियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से है, विशेष रूप से आभासी स्थानों में। इसका मतलब कुछ कारणों से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या सेवाओं तक पहुंच सीमित करना भी हो सकता है। यह विचार और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि समाज संचार, कार्य, मनोरंजन और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इंटरनेट और डिजिटल प्रणालियों पर तेजी से निर्भर हो रहा है। ₹गिरफ्तारी₹ शब्द आम तौर पर कानून प्रवर्तन द्वारा शारीरिक संयम को संदर्भित करता है। हालाँकि, जब डिजिटल दुनिया पर लागू किया जाता है, तो इसका एक अलग अर्थ हो जाता है। डिजिटल गिरफ्तारी में प्रतिबंध भौतिक नहीं बल्कि आभासी होता है। इसमें किसी की सोशल मीडिया तक पहुंच को निलंबित करना, उनके खातों को लॉक करना, इंटरनेट सेवाओं को ब्लॉक करना या यहां तक कि उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए निगरानी उपकरणों का उपयोग करना जैसे उपाय शामिल हैं। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन नियमों का उल्लंघन, आपराधिक व्यवहार का संदेह या वर्चुअल स्पेस में कानूनों को लागू करने के प्रयास शामिल हैं। डिजिटल गिरफ्तारी स्वैच्छिक या अनैच्छिक हो सकती है। कुछ मामलों में, लोग या संगठन अपनी डिजिटल गतिविधियों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करना चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ब्रेक लेने या अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सोशल मीडिया खातों को निष्क्रिय कर सकता है। दूसरी ओर, अनैच्छिक डिजिटल गिरफ्तारी तब होती है जब कोई बाहरी प्राधिकरण प्रतिबंध लगाता है। इसमें सरकारी एजेंसियां, कंपनियां या यहां तक कि किसी अन्य की डिजिटल उपस्थिति को नियंत्रित करने की तकनीकी क्षमता वाले निजी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी की वृद्धि डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार से निकटता से जुड़ी हुई है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई है, सरकारों और संगठनों ने डिजिटल व्यवहार की निगरानी और नियंत्रण के लिए परिष्कृत उपकरण विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में एल्गोरिदम होते हैं जो हानिकारक सामग्री का पता लगाते हैं और चिह्नित करते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता बार-बार सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसका खाता निलंबित या स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालाँकि इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना है, लेकिन ये निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते हैं। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि कौन निर्णय लेता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नियम समान रूप से लागू होते हैं। दुनिया भर की सरकारों ने भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाया है। निगरानी प्रणालियाँ व्यक्तियों के ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक कर सकती हैं, जिसमें उनके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटें, उनके द्वारा भेजे गए संदेश और उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री शामिल है। कुछ देशों में, अधिकारी संभावित खतरों की पहचान करने, अपराधों को रोकने और नियमों को लागू करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, गलत सूचना फैलाने के संदेह वाले किसी व्यक्ति को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि इन उपायों का उद्देश्य समाज की रक्षा करना है, लेकिन ये गोपनीयता और शक्ति के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के क्षेत्र में कंपनियां एक और प्रमुख खिलाड़ी हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के पास डिजिटल संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने की शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी प्लेटफ़ॉर्म की सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी उनके खाते को ब्लॉक या प्रतिबंधित कर सकती है। इसमें सामग्री पोस्ट करने, दूसरों के साथ बातचीत करने या यहां तक कि प्लेटफ़ॉर्म तक पूरी तरह से पहुंचने की उनकी क्षमता को सीमित करना शामिल हो सकता है। कंपनियां वित्तीय कारणों से भी प्रतिबंध लगा सकती हैं, जैसे सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर खातों को निलंबित करना। डिजिटल गिरफ्तारी व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। संगठन और यहाँ तक कि संपूर्ण क्षेत्र भी ऐसा कर सकते हैंडिजिटल प्रतिबंधों का अनुभव करें। उदाहरण के लिए, सरकारें विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अशांति या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के जवाब में कुछ वेबसाइटों या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक पहुंच को अवरुद्ध कर सकती हैं। ऐसा अक्सर सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और गलत सूचना या असहमति के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है। हालाँकि ऐसे उपाय कभी-कभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित कर सकते हैं और संचार में बाधा डाल सकते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी का एक अन्य पहलू साइबर अपराध को संबोधित करने में इसकी भूमिका है। जैसे-जैसे इंटरनेट आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, यह आपराधिक गतिविधियों का स्थान भी बन गया है। साइबर अपराधी हैकिंग, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं। इन खतरों से निपटने के लिए, अधिकारी अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। कुछ मामलों में, इसमें किसी संदिग्ध की डिजिटल उपकरणों या नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल हो सकता है। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां महत्वपूर्ण हैं लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के साथ संतुलित होनी चाहिए। डिजिटल गिरफ्तारी सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण भी हो सकती है। कार्यकर्ता और संगठन कभी-कभी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ डिजिटल प्लेटफार्मों या सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना बंद कर सकते हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि यह हानिकारक सामग्री को बढ़ावा देता है या उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। स्वैच्छिक डिजिटल गिरफ्तारी का यह रूप कंपनियों और सरकारों पर नैतिक प्रथाओं को अपनाने के लिए दबाव डालने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसके संभावित लाभों के बावजूद, डिजिटल गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण कमियां हैं। एक बड़ी चिंता दुरुपयोग की संभावना है। सत्ता में बैठे लोग आलोचकों को चुप कराने, असहमति को दबाने या विशिष्ट समूहों को निशाना बनाने के लिए डिजिटल प्रतिबंधों का उपयोग कर सकते हैं। यह उन देशों में विशेष रूप से चिंताजनक है जहां बोलने की स्वतंत्रता सीमित है और प्राधिकार पर कमजोर नियंत्रण है। ऐसे मामलों में, डिजिटल गिरफ्तारी सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के साधन के बजाय उत्पीड़न का एक उपकरण बन सकती है। एक अन्य चिंता व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर डिजिटल गिरफ्तारी का प्रभाव है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से कट जाना अलग-थलग और परेशान करने वाला महसूस हो सकता है। लोग अपने प्रियजनों के साथ संपर्क में रहने, जानकारी हासिल करने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए इंटरनेट पर भरोसा करते हैं। जब यह पहुंच छीन ली जाती है, तो इसका उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गंभीर परिणाम हो सकता है। इसके अलावा, डिजिटल प्रतिबंध शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को सीमित कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भर हैं। डिजिटल गिरफ्तारी कानूनी और नैतिक सवाल भी उठाती है। डिजिटल प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है और किन परिस्थितियों में? दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय मौजूद हैं? व्यक्ति अनुचित या मनमाने कार्यों को कैसे चुनौती दे सकते हैं? ये जटिल मुद्दे हैं जिन पर सरकारों, संगठनों और समग्र रूप से समाज के बीच सावधानीपूर्वक विचार और निरंतर बातचीत की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, डिजिटल गिरफ्तारी के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और नियम स्थापित करना आवश्यक है। डिजिटल व्यवहार की निगरानी और नियंत्रण के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएँ बनाने के लिए सरकारों और संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रतिबंध वैध कारणों पर आधारित हों, निष्पक्ष रूप से लागू हों और समीक्षा के अधीन हों। साथ ही, व्यक्तियों की निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच के अधिकारों की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल गिरफ्तारी की जटिलताओं से निपटने में शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण हैं। लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिएई डिजिटल स्पेस, साथ ही उनके कार्यों के संभावित परिणाम। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर, समाज व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग करने और उन स्थितियों से बचने के लिए सशक्त बना सकता है जो प्रतिबंध का कारण बन सकती हैं। डिजिटल गिरफ्तारी हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे लागू किया जाता है। हालाँकि यह सुरक्षा बढ़ाने, नियमों को लागू करने और डिजिटल युग में चुनौतियों का समाधान करने के अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह गोपनीयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए जोखिम भी पैदा करता है। जैसे-जैसे हम इस उभरते परिदृश्य को आगे बढ़ाते हैं, डिजिटल गिरफ्तारी के लाभों और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि यह व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए समाज के हितों की सेवा करता है।

# गणित विषय सीखने की ट्रिक

विजय गर्ग

कमजोर विद्यार्थियों के लिए गणित सीखने के गुर मैं गणित में अच्छा नहीं हूं' या 'त्रिकोणमिति के प्रश्नों को कैसे हल करूं?' ऐसे प्रश्न छात्रों के मन में उठते हैं और 'गणित का डर' उन्हें विषय में असफल होने के बुरे सपने देता है। यदि छात्र गणित की अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पेपर में सफलता की संभावना पर संदेह होने लगता है। छात्रों के सामने आने वाली आम समस्या कठिन प्रश्नों को हल करना और त्वरित गणना करना है जो केवल नियमित अभ्यास से ही संभव हो सकता है। इसके अलावा, यदि किसी छात्र को पहले से ही गणित में खराब ग्रेड मिल रहे हैं तो विषय में फेल होने का डर अपने चरम पर होता है। हर छात्र जिसे गणित की परीक्षा देनी होती है, वह कठिन सवालों का सामना करने का साहस जुटाता है। गणित के लिए छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य समस्याओं पर यहां चर्चा की गई है - गणित के पेपर के लिए छात्रों की सामान्य समस्याएं – गणित का प्रश्नपत्र देखकर वे शून्य हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं वे प्रश्न हल करते समय छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं विश्लेषण और तैयारी युक्तियाँ कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों के बीच अंतर – एक छात्र जो गणित में प्रतिभाशाली है, उसे प्रश्नों के प्रकार के बारे में पता चल जाता है और वह एक अध्याय से केवल एक या दो प्रश्नों को हल करके उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेता है। और जो छात्र गणित में कमजोर होते हैं वे भ्रमित हो जाते हैं और जल्द ही प्रश्नों को आधे में ही हल करना छोड़ देते हैं। कमजोर छात्रों को प्रत्येक प्रश्न के लिए मूल अवधारणा का उल्लेख करना होगा। हालाँकि, जो छात्र गणित में तेज़ हैं, वे केवल एक बार में ही अवधारणा को समझने के बाद प्रश्नों को तुरंत चुन लेते हैं। स्व-अध्ययन युक्तियाँ टॉपर्स की तरह गणित से कैसे निपटें? अधिक अभ्यास करें- गणित एकमात्र ऐसा विषय है जहां सिद्धांत सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संख्यात्मक की सत्यता को हल करना, इसलिए जो छात्र गणित में कमजोर हैं उन्हें गणित में अपनी गति और सटीकता बढ़ाने के लिए जितना संभव हो उतने प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है। मानसिक गणना का उपयोग करें - छात्रों को प्रश्नों के मूल भागों को हल करने के लिए मानसिक गणना या योग्यता का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि छात्र जटिल गणनाओं में फंस जाते हैं लेकिन सरल अंकगणित की मानसिक गणना से भी वे अपना अतिरिक्त समय और प्रयास बचा पाएंगे। टॉपर छात्र इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि गणित विषय के लिए वे संख्याओं के साथ खेलने और त्वरित और सटीक गणना करने के लिए मानसिक गणना करते हैं। अवधारणाओं को विभाजित करें - जो छात्र गणित में कमजोर हैं उन्हें गणित में महारत हासिल करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उन्हें एक अवधारणा से प्रश्नों को तीन भागों में विभाजित करना होगा - आसान- सीधे प्रमेयों और सूत्रों पर आधारित प्रश्न। मध्यम - 2 या अधिक अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न। कठिन प्रश्न - लंबे और समय लेने वाले प्रश्न जिन्हें विभिन्न रणनीतियों के साथ हल करने की आवश्यकता होती है; उदाहरण के लिए संभाव्यता अध्यायों में प्रश्न। प्रश्नों को हल करने के लिए नई तरकीबें न अपनाएं - छात्रों को यह समझने की जरूरत है कि गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जहां प्रश्नों को हल करने के लिए सीखने के तरीकों और तकनीकों में बदलाव दुर्लभ हैं। हम उन तरीकों को अपना रहे हैं जो गणित विशेषज्ञों ने हमें दशकों से सिखाए हैं। हालाँकि, गणित सीखने के लिए वैदिक गणित जैसी दिलचस्प और मजेदार तरकीबें हैं, लेकिन जिन छात्रों को इसकी अच्छी जानकारी नहीं है, उन्हें अपनी परीक्षा के दौरान इसे आज़माना नहीं चाहिए। गणित सीखने की ऐसी विधियों का अभ्यास तब किया जाना चाहिए जब छात्रों के पास पर्याप्त समय हो और वे कुछ नया और दिलचस्प सीखना चाहते हों। परीक्षा के डर से निपटने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रभावी टिप्सबोर्ड परीक्षाओं में निष्कर्ष: जो छात्र गणित से डरते हैं लेकिन उन्हें परीक्षा में इस विषय की परीक्षा देनी होती है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इस चुनौती से पार पाने के लिए एक योजना और रणनीति विकसित करनी चाहिए। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें छात्र अगर सही फॉर्मूला और विधि लागू करें तो आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अपने गणित के डर को दूर करने और विषय पर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यहां बताए गए सुझावों का उपयोग करें।

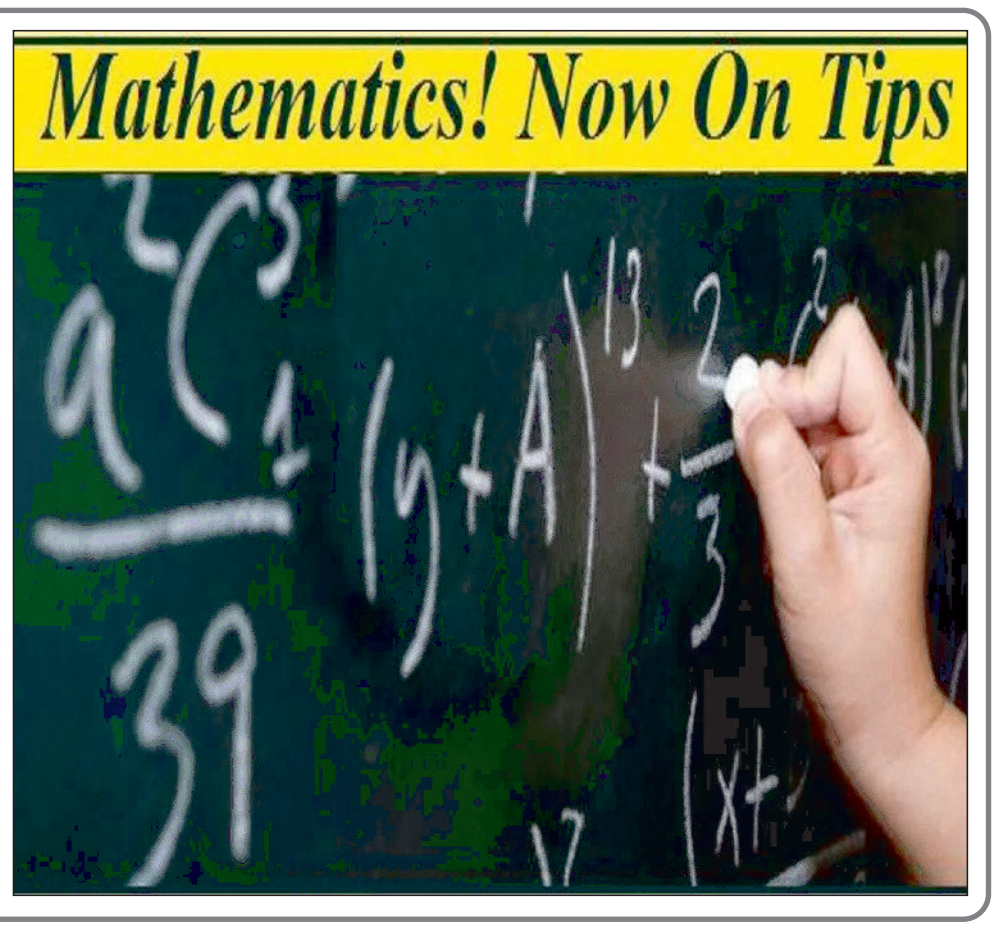

# सफल या असफल... कैसे भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में याद किए जाएंगे शक्तिकांत दास ?

परिवहन विशेष न्यूज

शक्तिकांत दास का आरबीआई गवर्नर के तौर पर 6 साल का कार्यकाल मंगलवार यानी 10 दिसंबर को खत्म हो गया। उनकी जगह संजय मल्होत्रा ने आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाल लिया है। दास के कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी आई। यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक का संकट आया। लेकिन शक्तिकांत दास की अगुआई में आरबीआई ने इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया।

**नई दिल्ली।** 'शक्तिकांत दास के जाने से अनिश्चितता आई है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ऐसी नीतियां अपनाई गई थीं, जिनसे रुपये में बड़ी गिरावट नहीं आई।' विदेशी मुद्रा व्यापारियों की यह पहली प्रतिक्रिया थी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को सेवा विस्तार न मिलने पर। इससे काफी हद तक शक्तिकांत दास के नीतिगत नजरिए की झलक मिलती है। उनका सबसे अधिक फोकस महंगाई को काबू करने, रुपये को मजबूत रखने और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने पर रहा।

**दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले आरबीआई गवर्नर**

अगर शक्तिकांत दास को सेवा विस्तार मिलता, तो उनके नाम सबसे लंबे वक्त तक आरबीआई गवर्नर का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। दास 2,190 दिन तक केंद्रीय बैंक के प्रमुख रहे। आरबीआई चीफ के तौर पर इससे ज्यादा वक्त सिर्फ बेनेगल रामा राव ने बिताया। उनका कार्यकाल 2,754 दिनों का था। वह जुलाई 1949 से जनवरी 1957 तक आरबीआई गवर्नर रहे थे।

**क्या ब्याज दरों पर दास का रवैया सबसे सख्त था?**

दास की यह छवि उनके कार्यकाल के आखिरी दौर में बन गई थी। उन्होंने महंगाई को काबू में रखने के लिए फरवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। यहां तक कि दिसंबर की एमपीसी से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तीन केंद्रीय मंत्रियों ने ब्याज दरों में कटौती का सुझाव दिया। लेकिन, दास की अगुआई वाली मॉनेटरी कमेटी ने ब्याज दरों को लगातार 11वीं बार जस का तस रखा।

इससे दास की छवि बन गई कि वह ऊंची ब्याज दर रखने के हिमायती हैं। ऐसे में यह याद करना जरूरी है कि खुद दास ने कोविड के शुरुआती दौर में ब्याज दरें बढ़ाने से मना कर दिया था। उस वक्त महंगाई दर आरबीआई के टारगेट से काफी ऊपर थी। जब कोरोना पीक पर था, तो आरबीआई ने अक्टूबर 2021 की एमपीसी मीटिंग में मौद्रिक नीति में ढील भी दी। उस वक्त दास ने कहा था कि हम किसी रूलबुक के गुलाम नहीं हैं।

**दास की बतौर RBI गवर्नर उपलब्धियां क्या रहीं?**

शक्तिकांत दास 2023 और 2024 में लगातार दो बार दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए। यह अवॉर्ड अमेरिका के वॉशिंगटन D.C. में ग्लोबल फाइनेंस देती है। उन्हें महंगाई पर कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी में स्टेबिलिटी और ब्याज दरों पर वाजिब नियंत्रण के लिए अवॉर्ड मिला था।

दास ने कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व में तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। कोरोना के दौरान दास के अगुआई में RBI ने लिक्विडिटी और एसेट क्वालिटी को बनाए रखने के लिए खास प्रयास किए। कई आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया गया।

दास ने यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को दिवालिया होने से बचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने IL&FS संकट का भी काफी अच्छे तरीके से सामना किया। उन्होंने दूसरी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) का भी IL&FS जैसा हाल होने से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए।

दास ने आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में जरूरी बदलाव किया 2018 में जब दास ने कार्यभार संभाला था, तब रेपो रेट 6.50 फीसदी पर थी। दास इसे घटाकर 4 फीसदी पर ला दिया। बाद में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसे फिर से बढ़ाकर 6.50% कर दिया।

दास के कार्यकाल के दौरान बैंकों का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA सितंबर 2024 तक 2.59 फीसदी के स्तर पर आ गया। यह दिसंबर 2018 में यह 10.38 फीसदी के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। यह दास से पहले के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और रघुराम राजन के लिए बड़ी चुनौती थी।

दास के कार्यकाल में बैंकों के बिजनेस में भी काफी सुधार हुआ। वे घाटे से मुनाफे में आ गए। बैंकों को वित्त वर्ष 2023 में 2.63 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। वहीं. वित्त वर्ष 2018 में बैंक 32,400 करोड़ रुपये के घाटे में थे।

## गेहूं के भाव अब नहीं होंगे बेकाबू, सरकार ने स्टॉक रखने के लिए सख्त किए नियम

गेहूं पर स्टॉक सीमा पहली बार 24 जून को लगाई गई थी। इसके बाद समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए 9 सितंबर को मानदंडों को कड़ा करने के लिए संशोधित किया गया था। अगर संस्थाओं के पास स्टॉक तय सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर मात्रा को निर्धारित स्टॉक लिमिट के भीतर लाना होगा।

**नई दिल्ली।** सरकार गेहूं की जमाखोरी रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि कीमतों को बेकाबू होने से रोका जा सके। यही वजह है कि सरकार ने थोक विक्रेताओं और प्रोसेसिंग करने वालों के लिए नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है।

खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को संशोधित करने का फैसला किया है।"

**अब कितना स्टॉक रख सकेंगे विक्रेता**

संशोधित मानदंडों के अनुसार, थोक विक्रेताओं को अब 2,000 टन के बजाय 1,000 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है। वहीं खुदरा विक्रेता प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन के बजाय 5 टन रख सकते हैं। यही लिमिट बड़ी चेन के खुदरा विक्रेताओं के लिए भी है।

गेहूं से ब्रेड और बिस्कुट जैसी खाने-पीने का सामान बनाने वाले प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए भी नियम सख्त हुए हैं। वे अप्रैल 2025 तक शेष महीनों से गुणा करके अपनी मासिक स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत रख सकते हैं।

**गेहूं पर कब लगी थी स्टॉक लिमिट**

गेहूं पर स्टॉक सीमा पहली बार 24 जून को लगाई गई थी। इसके बाद समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए 9 सितंबर को मानदंडों को कड़ा करने के लिए संशोधित किया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना होगा। उन्हें और हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना जरूरी है।

**लिमिट से ज्यादा स्टॉक है तो?**

अगर संस्थाओं के पास स्टॉक तय सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर मात्रा को निर्धारित स्टॉक लिमिट के भीतर लाना होगा। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई जाती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य मंत्रालय कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। यह बंदिश गेहूं की नई फसल आने तक जारी रहने का अनुमान है। लिमिट हटाने के लिए भी सरकार यह देखेगी कि गेहूं का उत्पादन कितना रहता है।

## जारी रहेगी नीतिगत निरंतरता, पदभार संभालने के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिया संदेश

मल्होत्रा ने वित्तीय समावेशन को आरबीआइ के एक अहम उद्देश्य के तौर पर चिन्हित किया। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया कि बैंकिंग सेक्टर में और आरबीआई के कार्यकलाप में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। आरबीआई के नए गवर्नर ने पहले दिन ही केंद्रीय बैंक की गतिविधियों से जुड़ी कई अहम बैठकों मे हिस्सा लिया है।

**नई दिल्ली।** आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने एक अहम संदेश यह दिया कि केंद्रीय बैंक की नीतिगत निरंतरता जारी रहेगी। हालांकि, जो भी चुनौतियां पेश आएंगी उसको लेकर आरबीआई पहले की तरह सतर्क बना रहेगा।

खासतौर पर अभी जिस तरह की वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक हालात को देखते हुए ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। एक दिन पहले गवर्नर पद से सेवानिवृत्त होने वाले डॉ. शक्तिकांत दास ने भी तकरीबन यही बातें कही थीं।

मुंबई स्थित आरबीआई के कार्यालय में पदभार संभालने के कुछ ही देर बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में मल्होत्रा ने कहा, 'स्थिरता काफी जरूरी है। टैक्सेशन से संबंधित नीति हो या मौद्रिक नीति या कोई और नीति हर जगह स्थिरता व निरंतरता को बनाए रखना जरूरी होता है।'

उन्होंने कहा कि आरबीआई जैसे संस्थान के लिए भरोसा भी काफी महत्वपूर्ण होता है। चुनौतियों को देखते हुए हमें सतर्क रहना होगा। आरबीआई की परंपरा रही है कि वह वित्तीय संस्थानों, सरकारों व अन्य सभी नियामक एजेंसियों से विमर्श करता रहता है तो इसे भी बरकरार रखा जाएगा।'

**ब्याज दरों में कटौती पर पर क्या होगा फैसला?**

हर सेक्टर से संबंधित लोगों से विमर्श को नए गवर्नर ने खासतौर पर चिन्हित किया। मल्होत्रा ने वित्तीय समावेशन को आरबीआई के एक अहम उद्देश्य के तौर पर चिन्हित किया। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया कि बैंकिंग सेक्टर में और आरबीआई के कार्यकलाप में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है।

बताया गया है कि आरबीआई के नए गवर्नर ने पहले दिन ही केंद्रीय बैंक की गतिविधियों से जुड़ी कई अहम बैठकों मे हिस्सा लिया है। उनकी अगुआई में मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक फरवरी, 2025 में होनी तय है। इसमें ब्याज दरों को घटाने को लेकर फैसला होने के कयास लगाये जा रहे हैं।

**कौन हैं संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra)?**

संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उन्हें अक्टूबर 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे। वह सरकारी कंपनी REC लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं।

मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। अपने तीन दशक के करियर में मल्होत्रा पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में सेवाएं दे चुके हैं।

## दो साल में बदल जाएगी सोलर इंडस्ट्री, सिर्फ 'मेड इन इंडिया' सौर सेल का होगा इस्तेमाल

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकार की समर्थिक परियोजनाओं नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स और ओपेन एक्सेस वाली रिन्यूएबल ऊर्जा की परियोजानओं के लिए इस सूची में शामिल कंपनियों से ही सौर उर्जा उपकरणों की खरीद करनी होगी। सरकार अभी तक इस सूची को इसलिए जारी नहीं कर रही थी कि देश मे सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या बहुत ही कम थी।

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जून, 2026 के बाद देश में लगने वाली किसी भी (सरकारी या निजी) सोलर परियोजना में सिर्फ भारत में उत्पादित सोलर मॉड्यूल्स या सोलर सेल्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अप्रूव्ड मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक आर्डर (एएलएमएम-2019) में अनिवार्य संशोधन कर आवश्यक प्रावधान किये हैं।

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि यह संशोधन भारतीय सौर ऊर्जा सेक्टर के लिए और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इसने एएलएमएम फ्रेमवर्क के तहत सोलर टीवी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बहुप्रतीक्षित सूची है। इस सूची में शामिल कंपनियों से ही जून, 2026 के बाद सोलर मॉड्यूल्स व सेल्स की आपूर्ति की जाएगी।

सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकार की समर्थिक परियोजनाओं, नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स और ओपेन एक्सेस वाली रिन्यूएबल ऊर्जा की परियोजानओं के लिए इस सूची में शामिल कंपनियों से ही सौर उर्जा उपकरणों की खरीद करनी होगी। सरकार अभी तक इस सूची को इसलिए जारी नहीं कर रही थी कि देश मे सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या बहुत ही कम थी और इस बात की अनिश्चितता थी कि वह घरेलू परियोजनाओं की मांग को पूरा कर सकेंगी या नहीं।

लेकिन सरकार की तरफ से व्यापक जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी करने के बाद और इन कंपनियों की उत्पादकता व गुणवत्ता की जांच के बाद यह विश्वास हो गया है कि घरेलू उद्योग आवश्यक मांग को पूरा कर सकेगा। यह भी बताया गया है कि भारत एक वैश्विक स्तर का सोलर सप्लाई चेन स्थापित

करने के लिए तैयार है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा और आयात पर भी निर्भरता कम करेगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत ने 13,200 मेगावाट क्षमता के सोलर मॉड्यूल्स का आयात किया है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 338 फीसद ज्यादा है। जबकि इसी दौरान सोलर सेल्स के आयात में 155 फीसद की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में भारत ने 51,460 करोड़ रुपये के सोलर सेल्स का आयात किया था और इसमें से तकरीबन 90 फीसद चीन से आया था।

चीन से आयातित सोलर सेल्स पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने के बावजूद उनका आयात नहीं थम रहा है। भारत की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता अभी 94 हजार मेगावाट है। वर्ष 2030 तक इस क्षमता को तीन लाख मेगावाट करने का लक्ष्य है। यानी दो लाख मेगावाट अतिरिक्त जोड़ना है।

आर्थिक शोध एजेंसी जीटीआरआई का कहना है कि वर्ष 2030 तक भारत को 30 अरब डॉलर का सोलर सेल्स का आयात करना पड़ सकता है। लेकिन अब एएलएमएम में संशोधन स्थिति बदल सकता है। आने वाले समय में देश में कोई भी सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी तो उसमें भारत निर्मित सेल्स व मॉड्यूल्स ही लगाए जाएंगे।

## अब बैंकॉक घूमने के लिए वीजा की टेंशन खत्म, थाईलैंड ने भारतीयों को दिया खास तोहफा

परिवहन विशेष न्यूज

थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के ल एि ई-वीजा शुरू करने का ऐलान क यिा है। इससे भारत का कोई भी पासपोर्टधारक ई-वीजा लेकर थाईलैंड घूम सकेगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात है कि वीजा के दिनों में कोई कटौती नहीं होगी। आप ई-वीजा लेकर भी थाईलैंड में 60 दिन तक ठहर सकेंगे। इसके लिए संबंधित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास ऑफलाइन भुगतान विकल्प दे रहे हैं। अगर आपने एक बार वीजा ले लयिा, तो उस पर लगने वाली फीस वापस नहीं होगी।

**नई दिल्ली।** अगर बैंकॉक घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए ई-वीजा शुरू करने का ऐलान कयिा है। यह सुविधा आपको अगले साल से मिलने लगेगी। फिर भारत का कोई भी पासपोर्टधारक ई-वीजा लेकर थाईलैंड घूम सकेगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात है कि वीजा के दिनों में कोई कटौती नहीं होगी। आप ई-वीजा लेकर भी थाईलैंड में 60 दिन तक ठहर सकेंगे।

रॉयल थाई दूतावास के मुताबिक, गैर-थाई नागरिकों को सभी तरह के वीजा के लिए https://www.thaievisa.go.th वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। इसमें आप आसानी से लॉगइन कर सकते हैं। आवेदकों को वीजा फीस देने के लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए संबंधित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास ऑफलाइन भुगतान विकल्प दे रहे हैं। अगर आपने एक बार वीजा ले लयिा, तो उस पर लगने वाली फीस वापस नहीं होगी।

**थाईलैंड में घूमने लायक जगहें**

थाईलैंड में सैलानियों के लिए घूमने लायक कई खूबसूरत जगहें हैं। इनमें बैंकॉक, पटाया और फुकेत जैसे तटीय इलाके हैं। वहीं, उत्तर में चियांग माई और दक्षिण में क्राबी भी हैं। क्राबी भी अपने खूबसूरत समुद्र तटों और समुद्र में पसरे पड़े बेमिसाल द्वीपों के लिए मशहूर है।

क्राबी में फुकेत व पटाया जैसी सैलानियों की भीड़ नहीं रहती। एकांत व सुकून की तलाश करने वाले लोगों के लिए यह सबसे बेहतर जगह रहेगी। क्राबी के निकट फीफी द्वीप का माया बे तो मानो कल्पनालोक सरीखा है। क्राबी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं हैं। आपको पहले राजधानी बैंकॉक ही जाना होगा।

बैंकॉक से 862 किलोमीटर दक्षिण में फुकेट है। थाईलैंड के इस सबसे बड़े द्वीप को अंडमान समुद्र का हीरा भी कहा जाता है। फुकेट प्रांत में कुल 40 छोटे-बड़े द्वीप हैं। मुख्य द्वीप उत्तर में दो पुलों के जरिये फांग नगा प्रांत से जुड़ा हुआ है। अंडमान समुद्र में फुकेट की जो बाकी तीन दिशाएं हैं उन्हें समुद्र की गहराइयां छानने के लिए बेहतरीन डाइविंग साइट्स में से एक माना जाता है।

टाइगर केव टेंपल यानी वाट थाम सुआ क्राबी शहर से तीन किलोमीटर दूर है। यहां की गुफाओं के भीतर चट्टानों पर बाघ के पंजों सरीखे निशान हैं। इसीलिए इन्हें टाइगर केव टेंपल कहा जाता है। आसपास की पहाड़ियों में कई गुफाएं हैं और खिरिवोंग घाटी में सैकड़ों साल पुराने वटवृक्ष हैं। बौद्ध साधना (मुख्यतया विपश्यना) का यह प्रमुख केंद्र ऐतिहासिक व पुरातात्विक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

## सरकार खोले राहत का पिटारा, गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेगी बूम

**नोएडा।** गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम को पूरे सेक्टर पर लागू किया जाए। अभी सरकार ने केवल मैन मेड फाइबर पर यह स्कीम लागू कर रखी है। बजट में पीएलआई का लाभ गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलता है तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

संयुक्त उद्यम के तहत तमाम विदेशी कंपनी इस सेक्टर में देशी उत्पादन इकाइयों का सहयोग करने के लिए आगे आएंगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, रोजगार की संभावनाएं प्रबल होगी। पिछले दिनों तमाम ऐसे सुझाव सरकार को दिए गए है, जिस पर अमल किया जाना चाहिए।

**इंडस्ट्री की क्या है डिमांड?**

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने बताया कि निर्यातकों को ऑर्डर पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है। इस पर सरकार की ओर से ब्याज में राहत देने के लिए इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम दी जाती थी, जो 30 सितंबर को समाप्त हो गई। इसको लंबी अवधि के लिए लागू रखना चाहिए। इसकी दर पहले की तरह पांच प्रतिशत की जाए।

उन्होंने कहा कि सेक्टर में तरह-तरह के नवाचार के लिए पिछली सरकारों ने टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लागू की गई थी, जिससे नई-नई मशीनों के लिए सब्सिडी दी जाती थी, जिसे बंद कर दिया गया। इस स्कीम को भी फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

**वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन**

नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के चेयरमैन ललित ठुकराल ने कहा कि सरकार घरेलू कंपनियों और प्रतिष्ठानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए सरकार वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुझाव सरकार के पास विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि चूंकि गारमेंट्स और टेक्सटाइल के क्षेत्र में नोएडा को हब माना जाता है और यह एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल है। इसलिए उम्मीद है कि बजट में सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार अवश्य सोच रही होगी।

## बनारसी साड़ी उद्योग को टेक्सटाइल पार्क की दरकार, सालाना 10 हजार करोड़ रुपये का है कारोबार

परिवहन विशेष न्यूज

श्रीकाशी विश्वनाथ का नव्य-भव्य धाम बनने के बाद बनारसी साड़ियों की खुदरा बिक्री बढ़ी हैं। बनारस के साड़ी दुपट्टा सूट उद्योग का सालाना कारोबार 10 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इस कारोबार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 8-10 लाख लोग जुड़े हैं। वहीं काशी में बनारसी वस्त्रों की 15 हजार से अधिक दुकानें हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

**नई दिल्ली।** अध्यात्म नगरी व देवाधिदेव की प्रिय काशी अब पूर्वांचल की सबसे बड़ी अर्थ नगरी भी बन गई है। बनारस की अर्थव्यवस्था बनारसी साड़ी व पर्यटन उद्योग पर आधारित है। अगर साड़ी का व्यापार मंदा होता है तो पूरा बनारस मंदी महसूस करने लगता है। अकेले बनारसी साड़ी के कारोबार से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आठ से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं।

बीते कुछ वर्षों में बनारसी साड़ी की मांग देश ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ी है। विशेष रूप से श्रीकाशी विश्वनाथ का नव्य-भव्य धाम बनने के बाद बनारसी साड़ियों की दुकानें तीन गुना बढ़ी हैं। वार्षिक कारोबार 10 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है।

हैंडलूम, पावरलूम संचालकों और कारोबारियों का कहना है कि यहां पर लखनऊ की तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क, अलग औद्योगिक क्षेत्र और भूमि व मशीन खरीद पर अनुदान मिले तो बनारसी साड़ी उद्योग को बहुत मदद मिलेगी। नव्य-भव्य बाबा धाम बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

यहां आने वाले देशी-विदेशी श्रद्धालु बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टा आदि की खरीदारी खूब कर रहे हैं। सबसे अधिक दक्षिण भारत के श्रद्धालु खरीदारी करते हैं। पहले होल सेल की बिक्री अधिक थी। पूरे देश के साथ-साथ विदेश तक आपूर्ति होती थी। अब घरेलू श्रद्धालु या पर्यटक यहां आ रहे हैं तो बनारसी वस्त्र खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इससे फुटकर बिक्री तो बहुत बढ़ी है, लेकिन थोक बाजार पर मामूली असर पड़ा है।

**धागों व रेशम का हो प्रबंध**

बनारसी साड़ी एक असंगठित उद्योग है, इसलिए बनारस में टेक्सटाइल पार्क की बहुत आवश्यकता है। सरकार को कोई ऐसा क्षेत्र डेवलप करना चाहिए, जहां इस उद्योग से जुड़ी मशीनें व हथकरघा आदि लगाए जा सकें। रेशम, जरी हो या पालिस्टर यार्न, बनारस के कारोबारी धागों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं।

बुनकरों को कच्चा माल सहजता से उपलब्ध हो, इसके लिए यहीं पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। एक हजार रुपये से अधिक मूल्य के वस्त्र पर 12 प्रतिशत जीएसटी है। स्कार्फ और दुपट्टा पर जीएसटी पांच प्रतिशत होना चाहिए। जो व्यापारी सिल्क व्यापार में बैंक ट्रांजेक्शन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड) के जरिये विदेशी मुद्रा अर्जित करते है, उन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप जीएसटी में भी छूट मिलनी चाहिए।

# कटक- भुवनेश्वर में डबल डेकर ई-बसें चलेंगी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

**भूबनेश्वर** :कटक - भुवनेश्वर-पुरी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भुवनेश्वर में चलेगी डबल डेकर बस! सीआरयूटी ने डबल डेकर ई-बसों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।सीआरयूटी ने निजी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित कीं। बताया गया है कि इसकी योजना खुर्दा, पुरी, कटक जिलों के लिए बनाई गई है। पहले चरण में 5 डबल डेकर बसें होंगी।डबल डेकर ई-बस का अनुबंध 10 साल के लिए होगा। आपूर्ति, संचालन, रखरखाव और स्टाफिंग एजेंसियां बसें उपलब्ध कराएंगी। सीआरयूटी ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर इस समझौते को अगले 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।भुवनेश्वर ने हाल ही में परिवहन के मामले में देश के अन्य शीर्ष शहरों को पीछे छोड़ दिया, जिससे पूरे राज्य को गर्व हुआ। नागरिकों की सुविधा के लिए, ओडिशा सरकार की राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन (सीआरयूटी) एमओबस और एमओई-राइड सेवाओं को देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भुवनेश्वर को 'सिटी विद' नाम दिया है देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक' का पुरस्कार परिवहन प्रणाली को मान्यता देने के लिए दिया गया। ओडिशा के आवास और शहरी विकास मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित तीन दिवसीय 17वें शहरी गतिशीलता भारत (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया।

# कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का प्रतिबंध

पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित तरीके से तकनीक से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करके कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं और वे सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों और संसाधनों की भी आवश्यकता है।

-प्रियंका सौरभ

सोशल मीडिया लोगों के बीच बातचीत के ऐसे माध्यम को संदर्भित करता है, जिसके ज़रिए वे वर्चुअल समुदायों और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, साझा और / या आदान-प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे कानून पेश करने की योजना की घोषणा की है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से रोकेगा। यह स्पष्ट है कि हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। संतुलन पर, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का मानना नहीं है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सही प्रतिक्रिया है। ऐसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध हैं, जो बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य मानवाधिकारों पर इतना महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना। वैकल्पिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण सोशल मीडिया कंपनियों पर देखभाल का कानूनी कर्तव्य रखना होगा। इसके लिए उन्हें अपने उत्पादों को बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उचित क़दम उठाने होंगे। देखभाल का वैधानिक कर्तव्य पेश करना सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने और सभी के लिए ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करने का एक सक्रिय तरीक़ा होगा। आयोग समझता है कि सरकार द्वारा देखभाल के ऐसे कर्तव्य पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं को साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री और ऑनलाइन शिकारियों सहित कई संभावित जोखिमों के संपर्क में लाता है। पहुँच को प्रतिबंधित करने से उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अध्ययनों से पता चलता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग स्वस्थ मस्तिष्क विकास, नींद और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है। प्रस्तावित कानून एक सुरक्षित विकासात्मक वातावरण का समर्थन करता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि उनका डेटा कैसे एकत्र किया जाता है, उपयोग किया जाता है या उसका मुद्रीकरण किया जाता है। युवा उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच पर प्रतिबंध लगाने से गोपनीयता के उल्लंघन और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के शोषण को कम करने में मदद मिल सकती है।

पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित तरीके से तकनीक से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करके कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं और वे सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों और संसाधनों की भी आवश्यकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्यक्तियों और संगठनों को पारंपरिक प्रचार या शैक्षणिक तरीकों से बेजोड़ गति से जानकारी साझा करने और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके को बदल दिया है। नतीजतन, यह निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया के फायदों में से एक यह है कि यह सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। सोशल मीडिया ने नागरिकों और उनकी चुनी हुई सरकार और राजनेताओं के बीच की खाई को कम किया है, जिससे लोकतंत्र में अधिक भागीदारी हुई है।

गलत सूचना के प्रसार का मुद्दा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान बनकर उभरा है। सोशल मीडिया के उदय ने दुनिया भर में कई किशोरों को नाम पुकारने, उत्पीड़न, शर्मिंदगी, अपमान, पीछा करने, धमकियों और यहाँ तक कि धोखाधड़ी के लिए उजागर किया है। व्यक्ति एक 'इंटरनेट व्यक्तित्व' बनाए रखने का प्रयास करते हैं जो किसी के जीवन की एक गुलाबी तस्वीर पेश करता है, फ़िल्टर का उपयोग करके उन हिस्सों को छुपाता है जिन्हें ' पर्याप्त नहीं माना जाता है। बार-बार सोशल मीडिया का उपयोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भावनाओं और सीखने से सम्बंधित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, २०२१. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्यवाही पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को संदेश के पहले स्रोत को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना होगा।

धारा 79 में कहा गया है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि मध्यस्थ, सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित किए जाने के बावजूद, प्रश्नगत सामग्री तक पहुँच को तुरंत अक्षम नहीं करता है, तो सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। एक व्यापक पारदर्शिता कानून की आवश्यकता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रासंगिक खुलासे को अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, सामग्री मॉडरेशन और सम्बंधित कार्य जैसे मानक सेटिंग, तथ्य-जांच और डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग को शामिल किया जाना चाहिए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में माता-पिता को अपने बच्चों को डिजिटल उपकरणों तक पहुँच प्रदान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए तथा उनके साथ स्वस्थ उपयोग के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

## जयपुर गुलाबी नगरी में तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भव्य स्वागत किया

# किशोरों में बढ़ती आक्रामकता चिंताजनक

(मनोज कुमार अग्रवाल-विनायक फीचर्स)

गोरखपुर में भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट की पत्नी की उनके ही नाबालिग बेटे ने हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि मां ने स्कूल जाने के लिए बेटे को जगा दिया था। गुस्से में उसने मां को धक्का दिया। उनका सिर दीवार से टकरा गया। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं, लेकिन बेटा उन्हें अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि मां को छोड़कर स्कूल चला गया। खून बहने से मां की मौत हो गई। 5 दिन तक मां की लाश के साथ रहा। छह दिन तक पत्नी से बात न होने पर साइंटिस्ट घर पहुंचे। दरवाजा खुला था और बदबू आ रही थी। अंदर गए तो देखा पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी। बेटे ने पिता-पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि गिरने की वजह से मां की मौत हुई। मगर जब पोस्टमॉर्टम हुआ तो लाश 6 दिन पुरानी निकली। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। यह वारदात नाबालिग किशोरों द्वारा पेशेवर अपराधियों की तर्ज पर अपराधिक वारदात करने की बढ़ती मनःस्थिति को उजागर करती है।

आज फिल्म स्क्रीन, ओटीटी प्लेटफार्म तथा सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई जाने वाली हिंसक सामग्री का किशोरों और युवाओं के मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है जिससे उनमें यौन अपराध तथा हिंसा की भावना कुलांचे भर रही है। पिछले एक महीने में किशोर बाल अपचारियों की करतूतों पर नजर डालें तो रूह कांप जाएगी।

12 नवम्बर को छतरपुर (मध्य प्रदेश) में एक युवक ने अपने पिता पूरन रैकवार को पीट-पीट कर मार डाला क्योंकि उसका पिता बचपन में उसे शरारत करने पर पीटा करता था तथा बड़ा होने पर उसकी शादी भी उसकी मनपसंद लड़की से नहीं करवाई जिसका बदला उसने इस प्रकार लिया।

14 नवम्बर को नालंदा (बिहार) के गांव छोटीआट में एक लड़की से छेड़छाड़ करने वाले नाबालिग को गांव के मुखिया कारू तांती द्वारा दंडित किए जाने पर उसने गुस्से में आकर अपने 2 साथियों के साथ मिल कर कारू तांती की हत्या कर दी।

23 नवम्बर को मुम्बई लोकल ट्रेन में सीट को लेकर हुए झगड़े में एक 16 वर्षीय किशोर ने अंकुश भालेराव नामक 35 वर्षीय एक यात्री की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। 27 नवम्बर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के 'हर्ष विहार' इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर देने के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पकड़ा। 5 दिसम्बर को दक्षिण दिल्ली में 'अर्जुन तंवर' नामक एक युवक ने अपने माता-पिता तथा बड़ी बहन की हत्या कर दी क्योंकि 'अर्जुन तंवर' हमेशा यह महसूस करता था कि उसके माता-पिता उसकी तुलना में उसकी बड़ी बहन को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। 5 दिसम्बर को ही दुर्ग (छत्तीसगढ़) के 'जेवरा' गांव में एक विवाह समारोह में रसगुल्ले को लेकर हुए विवाद के परिणामस्वरूप एक नाबालिग ने चाकुओं से वार करके सागर ठाकुर नामक युवक को मार डाला।

6 दिसम्बर को रायचोटी (आंध्र प्रदेश) में जिला परिषद उर्दू स्कूल में सैय्यद अहमद नामक एक अध्यापक द्वारा 3 छात्रों को कक्षा में शोर मचाने से मना करने पर उन्होंने अध्यापक सैय्यद अहमद पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। छह दिसम्बर को ही छतरपुर (मध्य प्रदेश) जिले के धमोरा गांव में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र सदम यादव ने अपने एक साथी के साथ मिल कर अपने स्कूल के प्रिंसिपल एस.के. सक्सेना की गोली मार कर हत्या कर दी। प्रिंसिपल ने सदम यादव को मात्र इतना समझाया था कि रबेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत।ह

सात दिसम्बर को कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के यारा गांव में पैसों के लेन- देन से तंग आकर शाहाबाद कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी दुष्यंत ने अपने माता- पिता और पत्नी की हत्या करने के बाद कोई जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली। आरोपी ने अपने 13 वर्ष के बेटे को भी जहर खिला दिया था लेकिन उसे बचा लिया गया।आठ दिसम्बर को नोएडा के मंगरोली गांव में नौवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा अपनी भाभी से शादी करने की खातिर अपने भाई की हत्या कर देने का मामला सामने आया। नाबालिग छात्र का कहना है कि उसके अपनी भाभी से अवैध संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था।

यह तो सिर्फ चंद वारदातों की बानगी है। लगातार ऐसी वारदातों की झड़ी लगी है कहीं जरा सी डांट-फटकार पर किशोर बुजुर्ग दादी दादा का कत्ल करने से नहीं चूक रहे हैं तो कहीं सरेराह गोली चाकू मारकर हत्या कर रहे हैं। कई बार शातिर अपराधियों के गिरोह किशोरों से हत्या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किशोर अपचारियों को कुछ समय सुधारगृह में रखकर छोड़ दिया जाएगा। किशोर अपचारियों के लिए बनाए गए कानून ही अब बाल व किशोरों को एक से बढ़कर एक संगीन अपराध करने के लिए गलत प्रेरणा का माध्यम बन गए हैं।

ओटीटी प्लेटफार्म , सोशल मीडिया पर अनियंत्रित हिंसा सेक्स की उलजलूल रील तथा फिल्मों में हिंसा के चित्रण से बाल मनोवेग दूषित हो रहा है। इसके अलावा युवाओं में बढ़ रही इस हिंसक प्रवृत्ति के अन्य प्रमुख कारणों में अभिभावकों की बच्चों के प्रति उदासीनता, धार्मिक व सामाजिक संगठनों की नकारात्मक भूमिका आदि शामिल हैं। आजकल हमारे समाज में बच्चों को नैतिकता, सदाचार और आत्मानुशासन सिखाने के स्थान पर झूठ, कपट और बिना मेहनत किए सुगम रास्ते से अधिकाधिक धन कमाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अतः इस समस्या से बचने के लिए न केवल शिक्षा संस्थानों में नैतिकता के आचरण को पाठ्यक्रम में शामिल कर उसके व्यवहारिक प्रशिक्षण को लागू करने की जरूरत है वहीं धार्मिक सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा । कर्मकांड और धार्मिक आचरण के साथ साथ मानवीय मूल्यों का महत्व जीवन में आत्मसात करने के लिए मानवता का पाठ पढ़ाने का पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए। अभिभावकों को भी शुरू से ही अपने बच्चों के आचरण को परख कर मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके आचरण को सुधारने की कोशिश करना चाहिए । बच्चे समाज के कर्णधार है, इनके चाल चरित्र की रक्षा करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

# त्वचा की क्लीज़िंग कैसे करें

(डॉ. फौजिया नसीम 'शाद'-विभूति फीचर्स)

स्वस्थ त्वचा के लिए क्लीजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वस्थ, सुंदर त्वचा तभी हो सकती है जब आप त्वचा की क्लींजिंग अच्छे से करें। नियमित रूप से दिन में दो बार क्लींजिंग की जानी चाहिए एक सुबह और दूसरी सोने से पूर्व ।क्लींज़िंग आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ अनेक त्वचा सम्बंधी समस्याओं से सुरक्षा भी प्रदान करती है। सही क्लींजर का प्रयोग त्वचा को स्वस्थ और समस्या मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । उपरोक्त लेख में कुछ उपयोगी होममेड क्लींजर की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें उपयोग कर आप भी अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं।

**होममेड क्लींजर**

●कच्चा दूध सबसे अच्छा क्लींजर है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की गहराई से सफाई करता है।

●त्वचा को साफ करने के लिए नमक

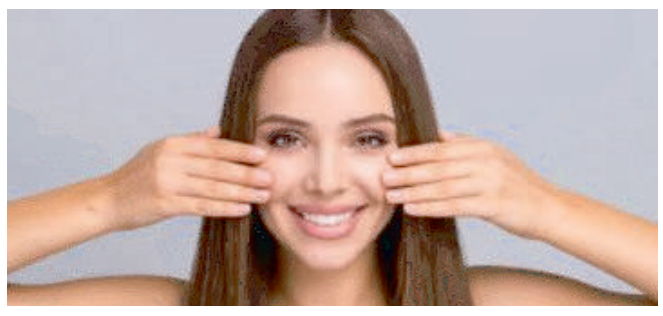

भी एक बेहतरीन क्लींजर है।

●नींबू का रस भी त्वचा को साफ करने वाला उपयोगी क्लींजर है।

●खीरे का रस भी एक बेहतर एस्ट्रिजेंट का काम करता है।

●दही में नींबू का रस मिक्स करके त्वचा पर लगाएं, ये भी तैलीय त्वचा के लिए उपयोगी क्लींजर है।

●सेब के छिलके त्वचा पर हल्के हाथों से मलें, ये क्लींजर त्वचा में कसाव लाने के साथ निखार भी लाता है।

●क्लींजिंग के लिए कच्चे आलू का रस भी उपयुक्त रहता है।

●त्वचा के निखार और उसकी क्लींजिंग के लिए केसर को दूध में मिक्स करके कॉटन की सहायता से त्वचा पर लगाएं।

●बेसन भी एक नेचुरल क्लींजर है जिसे आप गुलाब जल या मलाई के साथ भी प्रयोग कर सकती हैं।

●स्टीमिंग भी क्लींजिंग का अच्छा माध्यम है।

●नारियल का दूध त्वचा पर कॉटन की सहायता से लगाएं, दस मिनट के उपरांत त्वचा को ठंडे पानी से धो लें, इसके प्रयोग से त्वचा साफ होने के साथ निखर भी जाएगी।

***ध्यान रखें***

●त्वचा की कभी भी एक्स्ट्रा क्लींजिंग करने का प्रयास न करें वर्ना नेचुरल ऑयल खो जाएगा और त्वचा शुष्क नजर आएगी।

●सेंसेटिव त्वचा के लिए हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें, इसके प्रयोग से पोर्स खुल जाते हैं और त्वचा की सफाई अच्छे से हो जाती है।

●नार्मल और ड्राइ त्वचा पर साबुन का प्रयोग बिल्कुल न करें, इसके विपरीत क्लींज़िंग जेल , क्रीम या क्लींज़र का प्रयोग करें।

●शुष्क त्वचा पर शहद लगाएं। ये त्वचा की क्लींजिंग करने के साथ त्वचा की नमी को भी स्थापित रखता है।

●मुंहासे युक्त त्वचा पर टमाटर के रस में शहद मिक्स करके त्वचा पर लगाएं, पंद्रह मिनट के उपरांत त्वचा को धो लें, ये क्लींजर मुंहासे युक्त त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है।

## मुझे ऐसे ना भूलाया करो!

आप मुझे ऐसे ना भूलाया करो,
मैं भूलने की चीज ही नहीं हूँ।
मुझे कम-से-कम याद तो रखो,
मैं हृदय में समाने की चीज हूँ।
यार इतनी व्यस्तता अच्छी नहीं,
मैं याद करूँ आप भूल जाओ।

आप मुझे ऐसे ना भूलाया करो,
मैं भूलने की चीज ही नहीं हूँ।
ये मित्रता भी है ऐसी ही चीज,
बोए ही है हमने प्यार से बीज।
हम नहीं निकालते कोई खींज,
एक-दूजे पे जाते हैं हम रीझ।

आप मुझे ऐसे ना भूलाया करो,
मैं भूलने की चीज ही नहीं हूँ।
मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए,
विश्वास के जैसे हो दो पहिए।
जख्म एक-दूजे के भरते रहिए,
ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते जाइए।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्यप्रदेश)

## शिक्षा क्षेत्र में अपनी समाज के प्रतिभाओं का बढ़ाया मनोबल

तेलंगाना हैदराबाद सीरवी समाज की सामाजिक सेवा समिति श्री आईजी क्षत्रिय सीरवी विकास सेवा समिति संस्था ने अपने सीरवी समाज की प्रतिभाओं का शिक्षा के क्षेत्र में पांच प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाया है जिन्हें दिनांक 10 दिसम्बर 2024 राजस्थान जिला जोधपुर खारिया मीठापुर ( आईजी महाविद्यालय ) 21हजार दुसरा सहयोग बिलाड़ा ( Bed कॉलेज बोरुदा ) 11 हजार तीसरा सहयोग बिलाड़ा से ( Allen कोटा ) 21 हजार चौथा सहयोग खारिया मीठापुर ( श्री आईजी विद्या मंदिर ) 15 हजार दिनांक 11 दिसम्बर 2024 पांचवां सहयोग राजस्थान पाली सुमेरपुर बुसी 51000 लास्ट ईयर नर्सिंग टोटल 1,19000 का सहयोग सेवा समिति के माध्यम से प्रतिभाओं के कॉलेज में पहुंचाया गया 2025 में सेवा समिति कार्यकारिणी सदस्यों ने निर्णय लिया कि आगे भी इससे भी बढ़कर समाज के भामाशाहों के सहयोग से और सेवा समिति के माध्यम से प्रतिभाओं को सहयोग पहुंचाएंगे ताकि उनको यह एहसास ना हो कि हमारा परिवार कमजोर है इसलिए हमें नहीं पड़ा पा रहे हैं और सेवा समिति परिवार समाज के बंधुओं से यही अपेक्षा रखते है कि ऐसे ही सहयोग करते हैं सेवा समिति को ताकि सेवा समिति के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को सहयोग मिलता रहे।। जानकारी श्री आईजी क्षत्रिय सीरवी विकास सेवा समिति पदाधिकारी राष्ट्रीय संरक्षक रामलाल सैणचा गांधी धाम गुजरात व अध्यक्ष भेराराम सैणचा,माह सचिव व आवेदन जांच अधिकारी जगदीश सीरवी व संस्थापक गुदड़राम काग मैसुर जानकारी दी

## शिक्षा क्षेत्र में अपनी समाज के प्रतिभाओं का बढ़ाया मनोबल

सीरवी समाज की सामाजिक सेवा समिति श्री आईजी क्षत्रिय सीरवी विकास सेवा समिति संस्था ने अपने सीरवी समाज की प्रतिभाओं का शिक्षा के क्षेत्र में पांच प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाया है जिन्हें खारियामीठापुर ( आईजी महाविद्यालय ) 21हजार दुसरा सहयोग बिलाड़ा ( Bed कॉलेज बोरुदा ) 11 हजार तीसरा सहयोग बिलाड़ा से ( Allen कोटा ) 21 हजार चौथा सहयोग खारिया मीठापुर ( श्री आईजी विद्या मंदिर ) 15 हजार पांचवां सहयोग बुसी 51000 लास्ट ईयर नर्सिंग टोटल 1,19000 का सहयोग सेवा समिति के माध्यम से प्रतिभाओं के कॉलेज में पहुंचाया गया 2025 में सेवा समिति कार्यकारिणी सदस्यों ने निर्णय लिया कि आगे भी इससे भी बढ़कर समाज के भामाशाहों के सहयोग से और सेवा समिति के माध्यम से प्रतिभाओं को सहयोग पहुंचाएंगे ताकि उनको यह एहसास ना हो कि हमारा परिवार कमजोर है इसलिए हमें नहीं पड़ा पा रहे हैं और सेवा समिति परिवार समाज के बंधुओं से यही अपेक्षा रखते है कि ऐसे ही सहयोग करते हैं सेवा समिति को ताकि सेवा समिति के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को सहयोग मिलता रहे।।

# शांति का त्यौहार" कार्यक्रम बेंगलूरु कर्नाटक में प्रेम रावत के संदेश से प्रेरित हुए सैकड़ों लोग

**बेंगलूरू:** कर्नाटक राज विद्या केंद्र द्वारा बेंगलूरू के अंबेडर भवन में 'शांति का त्यौहार' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रेम रावत के संदेश का वीडियो प्रसारण किया गया, जिसमें प्रेम रावत ने कहा कि 'जब अँधेरा हो जाए आपके जीवन में और ऐसा लगे कि हर चीज़ ने आपको छोड़ दिया है, पर अगर आपका स्वांस आपके अंदर आ रहा है और जा रहा है तो वह शक्ति जो सारे विश्व को चला रही है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। वह हमेशा आपके साथ है। अगर सारी चीजें आपके विपरीत हो जाएं, पर अगर वह चीज आपके साथ है तो सबकुछ ठीक है। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है।

इस कार्यक्रम में सुन्दर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जिसमें नृत्य कविता गायन, भजन आदि सुन्दर प्रस्तुतियाँ भी थी। कार्यक्रम के दौरान एक नाट्य प्रस्तुति भी दी गई जो कि प्रेम रावत जी की प्रसिद्ध पुस्तक (तीर का लक्ष्य) की एक कहानी 'अभ्यास की शक्ति' पर आधारित थी। इस संदेश को वहाँ आए सभी श्रोताओं ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और आगे सुनने की इच्छा जाहिर की। इस कार्यक्रम ने लोगों को जीवन में शांति को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

प्रेम रावत जी एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षक, बेस्ट सेलिंग लेखक एवं मानवतावादी हैं और उन्होंने दो गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाए हैं। वे संपूर्ण विश्व में अपने श्रोताओं को वास्तव में अपने आपसे जुड़ने और संतुष्टि का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका संदेश उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, उन्होंने

पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय में 5500 से भी अधिक कार्यक्रमों को संबोधित किया है। उनका प्रेम रावत फाउंडेशन भारत में बंटोली (राँची) में जनभोजन, सुविधा भी संचालित करता है। जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को हर रोज पौष्टिक, स्थानीय भोजन और स्वस्थ पानी मिलता है। ऐसी ही सुविधाएँ नेपाल, केप टाउन और घाना में भी संचालित की जा रही है।

इसके अलावा टी पी आर एफ का पीस एजुकेशन प्रोग्राम वीडियो आधारित कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वयं की आंतरिक शक्ति और व्यक्तिगत शांति की खोज में मदद करना है। प्रत्येक कार्यशाला सम्मान, आंतरिक शक्ति, आत्म जागरूकता, स्पष्टता, समझ, गरिमा, चयन, आशा और तृप्ति जैसे विषयों पर केंद्रित है। इस प्रोग्राम से अब तक 84 देशों में 450,000 से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं। व्यक्तिगत उन्नति और शिक्षा पर पड़ने वाले इसके सकारात्मक प्रभावों के लिए इसकी बहुत अधिक सराहना की गयी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023